



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11052020-219340
CG-DL-E-11052020-219340

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 119]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 11, 2020/वैशाख 21, 1942

No. 119]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 11, 2020/VAISAKHA 21, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

प्राथमिक जांच परिणाम

नई दिल्ली, 11 मई, 2020

प्रकरण सं. एसजी - 08/2019

विषय : भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक प्रतिभागिता करार (द्विपक्षीय सुरक्षा उपाय) नियमावली, 2017 के तहत कोरिया से भारत में "फ्यैलिक एनहाइड्राइड" के आयातों के संबंध में द्विपक्षीय सुरक्षा जांच के प्राथमिक जांच परिणाम।

फा. सं. 22/8/2019-डीजीटीआर.—

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. भारत गणराज्य और कोरिया सरकार के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईपीए) के अनुच्छेद 2.22 और भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक प्रतिभागिता करार (द्विपक्षीय सुरक्षा उपाय) नियमावली, 2017 (जिसे यहां आगे "नियमावली" अथवा "द्विपक्षीय सुरक्षा नियमावली" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, मैसर्स आई जी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड और मैसर्स थिरूमलाई केमिकल्स लिमिटेड (जिन्हें यहां आगे "आवेदक" कहा गया है) ने कोरिया गणराज्य (जिसे यहां आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) से फ्यैलिक एनहाइड्राइड (पीएएन) (जिसे यहां आगे "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "संबद्ध सामान" भी कहा गया है) के बड़े हुए आयातों के संबंध में द्विपक्षीय सुरक्षा जांच की शुरुआत के लिए सीईपीए और द्विपक्षीय सुरक्षा नियमावली के अनुसार व्यापार सुधार महानिदेशक (जिसे यहां आगे "प्राधिकारी" अथवा "महानिदेशक" कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन पत्र दायर किया है।

2. प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर नियमावली के अनुसार जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र में प्रकाशित 1 अक्तूबर, 2019 की अधिसूचना संख्या एसजी-08/2019 जारी की।

ख. प्रक्रिया

3. जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

क. प्राधिकारी ने 1 अक्तूबर, 2019 की जांच की शुरुआत की प्रति वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा अन्य संबंधित मंत्रालयों में केंद्र सरकार, भारत में कोरिया गणराज्य के दूतावास के माध्यम से कोरिया सरकार, संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों तथा निर्यातकों और आवेदन पत्र में उल्लिखित ज्ञात आयातकों तथा अन्य पक्षकारों को उपर्युक्त नियमावली के नियम 5(2) के अनुसार भेजी।

ख. आवेदकों द्वारा दायर आवेदन पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रति वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा अन्य संबंधित मंत्रालयों में केंद्र सरकार, भारत में कोरिया गणराज्य के दूतावास के माध्यम से कोरिया सरकार और संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों तथा निर्यातकों को नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार उपलब्ध कराई गई थी।

ग. प्राधिकारी ने संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को द्विपक्षीय जांच शुरू किए जाने की सार्वजनिक सूचना की प्रति भेजी और नियमावली के नियम 5(4) के अनुसार निर्धारित स्वरूप एवं तरीके से प्रश्नावली का उत्तर दायर करने तथा तीस दिन के भीतर लिखित में अपने ज्ञात विचार देने का अवसर प्रदान किया:

- i. एक्युंग पेट्रोकेमिकल कं. लि.
- ii. एलजी पेट्रोकेमिकल, यियोचोन
- iii. हनवा केमिकल कारपोरेशन
- iv. ओसीआई कंपनी लिमिटेड

घ. जारी प्रश्नावली के उत्तर में चारों उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए।

ङ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 5(4) के अनुसार, आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक प्रश्नावली भेजी:

- i. क्रे वैली रेसिन्स इंडिया लि.
- ii. गुडलेस नेरोलेस पेंट्स लि.
- iii. गार्गी इंडस्ट्रीज
- iv. हिंदुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लिमिटेड
- v. केमराँक इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट्स लि.
- vi. शालीमार पेंट्स लिमिटेड
- vii. यू. के. पेंट्स इंडिया प्रा. लि.

च. उत्तर में, निम्नलिखित आयातकों ने प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं:

- i. संदीप ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लि.
- ii. यूनिटी ऑर्गेनिक्स प्रा. लि.
- iii. निशांत ऑर्गेनिक्स प्रा. लि.
- iv. धनलक्ष्मी पिगमेंट्स प्रा. लि.
- v. केसर पेट्रोप्रोडक्ट्स लि.
- vi. मजदा कलर्स लि.
- vii. शिव डाइस्टफ इंटरमीडिएट इंडस्ट्रीज

- viii. ए-वन फ़थैलो कलर्स प्रा. लि.
- ix. ए-वन केमिकल्स
- x. नारायण ऑर्गेनिक्स प्रा. लि.
- xi. नारायण इंडस्ट्रीज
- xii. पीसीएल ऑयल एंड सॉल्वेंट्स लि.
- xiii. केएलजे प्लास्टिसाइजर्स लि.
- xiv. रचना प्लास्टिसाइजर्स
- xv. पायल पॉलीप्लास्ट प्रा. लि.
- xvi. एशियन पेंट्स लिमिटेड
- xvii. कनसाई नेरोलेक पेंट्स लिमिटेड
- xviii. शालीमार पेंट्स लि.
- xix. बर्जन पेंट्स इंडिया लि.

छ. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को भी प्रश्नावली भेजी। घरेलू उद्योग ने अपने प्रश्नावली के उत्तर दायर किए।

ज. निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों ने जांच की शुरुआत की अधिसूचना का उत्तर देते हुए अनुरोध दायर किए:

- i. केमेक्सिल (बेसिक केमिकल्स, कॉस्मेटिक्स और डाइज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल)
- ii. द गुजरात डाइस्टफ मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन
- iii. एकुंग पैट्रोकेमिकल कं. लि., हनवा केमिकल कारपोरेशन, ओसीआई कंपनी लि., एलजी केम. लि. की ओर से कोरिया पैट्रोकेमिकल इंडस्ट्री एसोसिएशन।
- iv. कोरिया सरकार
- v. इंडियन पेंट एसोसिएशन
- vi. केएलजे प्लास्टिसाइजर्स लि., पायल पॉलीप्लास्ट प्रा. लि., रचना प्लास्टिक्स एंड पीसीएल ऑयल और सॉल्वेंट्स लि. की ओर से सामूहिक अनुरोध।

झ. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले में रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया।

ञ. अब तक हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों, जहां भी संगत पाए गए, पर इन प्राथमिक जांच परिणामों को जारी करते समय विचार किया गया है।

ग. आवेदकों द्वारा किए गए अनुरोध

4. आवेदकों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. जांचाधीन उत्पाद एचएस कोड 29173500 के तहत आने वाला "फ़थैलिक एनहाइड्राइड" है। विचाराधीन उत्पाद का प्रयोग सामान्यतः फ़थैलिक ईस्टर का उत्पादन करने के लिए किया जाता है, जो प्लास्टिसाइजर के रूप में काम करता है।
- ख. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित किया जा रहा उत्पाद आयातित उत्पाद की समान वस्तु है। घरेलू उत्पाद आयातित उत्पाद से तुलनीय है।
- ग. आवेदकों के अलावा, भारत में दो विद्यमान उत्पादक हैं अर्थात् एसआई ग्रुप लिमिटेड और एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स ने जुलाई, 2017 में अपना संयंत्र स्थायी रूप से बंद कर दिया है और उनका संयंत्र एक आवेदक मैसर्स थिरूमलाई केमिकल्स लिमिटेड द्वारा खरीद लिया गया है।

- घ. भारत कोरिया सीईपीए के अनुसरण में कोरिया से फथैलिक एनहाइड्राइड के आयातों पर शुल्क आठ वर्षों में शून्य तक कम किया गया है।
- ङ. आयात मात्राओं में काफी वृद्धि है। भारत में संबंधित उत्पाद के आयात पूर्ण दृष्टि से और उत्पादन, खपत और भारत में हिस्से के संबंध में काफी बढ़े हैं।
- च. कोरिया से भारत में आयातों को भारत कोरिया सीईपीए करार के तहत फथैलिक एनहाइड्राइड के लिए शुल्क लाभ है, अतः देश में कोरिया से अब संबद्ध सामानों की बाढ़ बन गई है।
- छ. भारतीय उद्योग के उत्पादन एवं बिक्री में हाल ही की अवधि में काफी गिरावट आई है। यद्यपि, उत्पाद के लिए मांग नहीं बढ़ी है, तथापि, आयातों में उछाल आया है, इस प्रकार घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है।
- ज. घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में 2019-20 की पहली तिमाही में गिरावट आई है।
- झ. उत्पादन तथा क्षमता उपयोग में गिरावट से यह सिद्ध है कि आयातों में वृद्धि से घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।
- ञ. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है, जबकि आयातों का बाजार हिस्सा बढ़ा है। बाजार हिस्सा तेजी से 2019-20 की पहली तिमाही में 50 प्रतिशत तक गिरा है।
- ट. संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों की काफी कटौती कर रहे हैं। आयात कीमतों में जांच की अवधि की पिछली दो तिमाहियों में तेजी से गिरावट आई है। इस प्रकार, यदि आयात बढ़ते रहे तो घरेलू उद्योग प्रसंस्करण लागतों को वसूल करने में भी सक्षम नहीं होगा और उसे काफी वित्तीय हानियां होंगी।
- ठ. घरेलू उद्योग के लाभ में इस अवधि के दौरान बिक्री की हानि को देखते हुए, 2018-19 की दूसरी तिमाही में *** लाख रुपये से 2019-20 की पहली तिमाही में *** लाख रुपये तक गिरावट आई है। घरेलू उद्योग के लाभ 2018-19 की दूसरी तिमाही तक बढ़ रहे थे।
- ड. भारतीय उद्योग की उत्पादकता में आरंभिक तौर पर सुधार हुआ है, परंतु जांच की अवधि में काफी गिरावट आई है।
- ढ. पहले ही हुई गंभीर क्षति के अलावा, आयात गंभीर क्षति का खतरा पैदा कर रहे हैं, जैसा कि निम्नलिखित से स्पष्ट होगा:
- सापेक्ष रूप से अल्पावधि में आयातों की मात्रा काफी बढ़ी है।
 - घरेलू बाजार में काफी हिस्सा आयातों द्वारा पहले ही लिया हुआ है और आयातों का हिस्सा बढ़ रहा है।
 - घरेलू कीमत और आयातित उत्पाद कीमत के बीच अंतर अत्यधिक है।
- ण. बढ़े हुए आयातों को छोड़कर, अन्य कोई कारक नहीं हैं जो घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण हो सकते हों।
- त. आयातों की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों से काफी कम है।
- थ. घरेलू उद्योग बिक्री के अवसर तथा सामान्य मार्जिन खो रहा है। परिणामस्वरूप, कम कीमत वाले आयातों की सतत मौजूदगी के कारण बिक्री, लाभ, निवेश पर आय और नकद प्रवाह में गिरावट आ रही है।
- द. बढ़े हुए आयातों से आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि और घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में कमी हुई है।
- ध. अनुरोध है कि कोरिया से आयातों में काफी वृद्धि हुई है जबकि घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री और परिणामस्वरूप क्षमता उपयोग में काफी गिरावट आई है।
- न. समायोजन योजनाओं के संबंध में, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि वे कीमतें कम करने के लिए उपाय कर रहे हैं। आईजी पैट्रोकेमिकल्स ने समायोजन योजना दी है जिसमें मौजूदा उत्प्रेरक को बदलकर कच्ची सामग्री लागत में कमी करने संबंधी कार्रवाई योजना, विद्युत एवं ईंधन लागत में वसूलियों की कमी में सुधार, क्षमता अभिवृद्धि तथा मौजूदा संयंत्रों की यूटिलिटियों को एकीकृत करने, प्रशासनिक खर्चों, कार्मिक लागत और वित्तीय लागत के निमित्त लागतों को कम करने के प्रयास शामिल हैं। थिरूमलाई केमिकल्स ने एक समायोजन योजना दी है जिसमें उच्चतम

क्षमता तथा दक्षता के लिए उपस्करों का उन्नयन कर लागत में कमी, उत्पादन में सुधार, ऊर्जा लागतों में कमी, तेल खपत में कमी, वेतन एवं मजदूरियों, भंडार तथा अतिरिक्त हिस्से-पुर्जों, मरम्मत एवं रख-रखाव तथा प्रशासनिक ऊपरी खर्चों में कमी शामिल है।

5. कोरिया पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री एसोसिएशन द्वारा किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:

- क. आवेदन पत्र में नियमावली की अपेक्षाओं को पूरा करने का कोई साध्य नहीं है।
- ख. घरेलू उद्योग के प्रमुख निष्पादन मानदंड क्षमता उपयोग, उत्पादन, बिक्री, लाभप्रदता कोई क्षति नहीं दर्शाते।
- ग. आवेदक यह दर्शाने में विफल रहे कि तथाकथित क्षति आयातों में वृद्धि तथा सीमा शुल्कों में कमी के कारण है। यह नहीं दर्शाया गया है कि आयातों में वृद्धि सीमा शुल्कों में कमी अथवा उन्हें समाप्त करने के कारण है तथा अकेले वृद्धि भारत कोरिया सीईपीए के अनुच्छेद 2.22 की अपेक्षा के अनुसार घरेलू उद्योग को क्षति का कारण है।
- घ. योजनागत क्षमता विस्तार में विलंब, योजनागत अल्पावधि बंदी, OX (ऑर्थोक्सिलीन) की कीमतों में अस्थिरता आदि से भी आवेदकों का निष्पादन प्रभावित हो सकता है।
- ङ. आवेदक की वार्षिक रिपोर्टों में चर्चाएं स्थिति में समग्र हास का कोई संकेत नहीं दर्शातीं।
- च. आवेदक को प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षति अवधि के लिए आंकड़े देने चाहिए। जिस अवधि के लिए आवेदन पत्र में आंकड़े दिए गए हैं, वे भ्रामक हैं।
- छ. थाइलैंड और इंडोनेशिया तथा जिनके साथ भारत का एफटीए है, से आयातों में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, ताइवान से आयातों में वृद्धि भी कोरिया से आयातों में वृद्धि के अनुरूप है।
- ज. आयातों में वृद्धि सीईपीए के तहत सीमा शुल्कों में कमी की अपेक्षा चीन जन. गण., इंडोनेशिया, इजराइल, रूस, ताइवान, थाइलैंड और संयुक्त अरब अमीरात से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति के अनुरूप है। आवेदन पत्र आयातों में वृद्धि के कारण के रूप में पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति के प्रभावों के संबंध में मौन है।
- झ. मांग-आपूर्ति के अंतराल को पूरा करने के लिए आयात आवश्यक हो गए थे।
- ञ. आवेदकों ने सितंबर, 2017 की अवधि तक क्षति के कारण के रूप में पाटन का दावा किया था।
- ट. यद्यपि, कोरिया गणराज्य से आयात भारतीय मांग के लगभग 23 प्रतिशत थे, तथापि, अन्य आयात लगभग 24 प्रतिशत मांग के हुए।
- ठ. घरेलू उद्योग का उत्पादन बढ़ा है। यह क्योर ऑयल तथा अन्य पेट्रोकेमिकल उत्पादों में अस्थिरता, सुदूर पूर्व में मंदी, यूएस-चीन व्यापार प्रतिबंध आदि मांग आदि को पूरा करने के लिए विस्तारों को पूरा करने में विलंब जैसे विभिन्न मुद्दों के बावजूद है।
- ड. घरेलू उद्योग की बिक्री 38 अंकों तक 2007-08 की तुलना में नवीनतम अवधि में बढ़ी है।
- ढ. घरेलू उद्योग की क्षमता में वृद्धि हुई है। जब घरेलू उद्योग गंभीर क्षति का दावा कर रहा हो, उस समय क्षमता में अभिवृद्धि को घरेलू उद्योग के क्षति संबंधी दावों को समाप्त करने वाले कारक के रूप में देखा जाना चाहिए।
- ण. आवेदकों की उत्पादन विस्तार योजनाएं घरेलू उद्योग के इस निर्णय का प्रतीक हैं कि उत्पादन और बिक्री मात्रा में निकट भविष्य में वृद्धि होगी जो इस बात की गारंटी देता है कि कोई गंभीर क्षति नहीं है जिसका कि घरेलू उद्योग द्वारा दावा किया गया है। वास्तविकता में एक सकारात्मक दृष्टिकोण है।
- त. आयात कीमतों में घरेलू उद्योग की कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति का अनुसरण करते हुए वृद्धि हुई है। आयातों की पहुँच कीमत में स्पष्ट रूप से घरेलू उद्योग को उनकी कीमतें कम करने के लिए मजबूर नहीं किया था। इसके विपरीत, एनएसआर बढ़ा है।
- थ. जब पाटनरोधी शुल्क लागू था तो घरेलू उद्योग अधिक लाभ कमा रहा था। वर्तमान लाभ में गिरावट, गिरावट नहीं है बल्कि अब सामान्य रूप से अधिक लाभों में सुधार है।

- द. लगभग दस वर्षों में दो रक्षोपाय तथा पाटनरोधी उपाय रहे हैं, और आवेदक अपने निष्पादन में सुधार लाने के लिए कोई कार्यनीति तैयार करने के बजाए व्यापार सुधारों के माध्यम से आयात प्रतिबंधों पर विश्वास करते हैं।
- ध. हाल ही में की गई पाटनरोधी शुल्क जांच में, क्षति संबंधी नकारात्मक निर्धारण किया गया था और क्षति की संभावना भी नकारी गई थी।
- न. जांच की शुरुआत में कहीं भी यह प्रकट नहीं किया गया है कि क्या घरेलू उद्योग ने ऐसी कोई समायोजन योजना प्रस्तुत की है कि वे उत्पादकता में सुधार, लागत में कमी तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा का सामना करने के लिए अपनी बिक्री कीमतों में कमी कैसे लाएंगे।
- प. कोई अप्रत्याशित स्थिति होनी चाहिए जिससे आयातों में वृद्धि हुई हो।

घ.2 कोरिया सरकार द्वारा किए गए अनुरोध

6. कोरिया सरकार द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - क. भारतीय घरेलू उद्योग की वर्तमान परिस्थितियां कोरिया-भारत सीईपीए के अनुच्छेद 2.24 के तहत परिभाषित अंतिम रक्षोपाय लगाए जाने की आवश्यकता की महत्वपूर्ण परिस्थितियों के लिए योग्य नहीं हैं।
 - ख. वर्तमान जांच प्रक्रियाबद्ध आधार पर रद्द की जानी चाहिए क्योंकि घरेलू उद्योग ने कोई समायोजन योजना नहीं दी है।
 - ग. आर्थिक मानदंडों का विश्लेषण घरेलू उद्योग को क्षति अथवा क्षति के खतरे का मामला नहीं बनाता।
 - घ. कोरिया गणराज्य से फ्यैलिक एनहाइड्राइड के आयातों की हाल में, अचानक, तीव्र तथा काफी वृद्धि नहीं हुई है।
 - ङ. आयातों में कोई भी तथाकथित वृद्धि कोरिया-भारत सीईपीए के तहत सीमा शुल्कों में कमी अथवा उनकी समाप्ति के परिणामस्वरूप नहीं है।
 - च. वर्तमान जांच को रद्द किया जाना चाहिए क्योंकि एक वैध द्विपक्षीय रक्षोपाय की महत्वपूर्ण अपेक्षाएं पूरी नहीं की गई हैं क्योंकि रक्षोपाय जांच के लिए अपेक्षित मानक काफी अधिक हैं।
 - छ. आवेदकों ने अपने आवेदन पत्र में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है क्योंकि जो आंकड़े पाटनरोधी जांच के अंतिम जांच परिणाम में उपलब्ध थे, उन्हें प्रकट नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, व्यापार सूचना संख्या 10/2018 की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया गया है।
 - ज. आवेदन पत्र में कमी है क्योंकि घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए आंकड़े जांच की शुरुआत की अधिसूचना में अभिज्ञात अवधि के अनुरूप नहीं हैं।
 - झ. अन्य देशों से आयातों में कोरिया से आयातों की तुलना में तीव्र दर पर वृद्धि हुई है।
 - ञ. रक्षोपाय संबंधी करार के अनुच्छेद 3.1 के अनुसार, एक सकारण एवं पर्याप्त स्पष्टीकरण होना चाहिए जो शुल्क में कमी और आयातों में आरोपित वृद्धि के बीच संबंध दर्शाए। प्राधिकारी को चाहिए कि वे सकारण स्पष्टीकरण का पता लगाएं और बताएं तथा उसे दर्शाएं।
 - ट. रक्षोपाय संबंधी करार के अनुच्छेद 2.1 और कोरिया-भारत सीईपीए के अनुच्छेद 2.22 की भाषा के अनुसार आयातों में कोई अचानक, काफी अथवा तीव्र वृद्धि नहीं है।
 - ठ. कोरिया-भारत सीईपीए के अनुच्छेद 2.22 की 4 अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया गया है और इसीलिए जांच को रद्द किया जाएगा।
 - ड. इजराइल, कोरिया और ताइवान से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति के फलस्वरूप भी आयात बढ़ सकते थे।
 - ढ. उत्पादन, बिक्री, बाजार हिस्सा, मालसूची, लाभ, नकद लाभ आदि के संदर्भ में आवेदकों का निष्पादन बढ़ा है।
 - ण. करार के अनुच्छेद 4.2(ख) तथा नियमावली के नियम 7 के अनुसार प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वे आयातों में वृद्धि और क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क की जांच करें और गैर-आरोपण विश्लेषण करें।
 - त. शुल्क लगाए जाने से दो देशों के आर्थिक संबंध कमजोर होंगे।

घ.3 इंडियन पेंट एसोसिएशन द्वारा किए गए अनुरोध

7. इंडियन पेंट एसोसिएशन द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. आवेदकों ने द्विपक्षीय रक्षोपाय जांच की शुरुआत के लिए शर्तें सिद्ध करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य नहीं दिए हैं। अनुच्छेद 2.22 में उल्लिखित चार शर्तें पूरी नहीं की गई हैं।
- ख. आवेदक ने जांच की शुरुआत की अधिसूचना में निर्धारित अवधि के लिए आंकड़े नहीं दिए हैं।
- ग. आवेदन पत्र में आरोपों की उपयुक्त समझ नहीं मिलती क्योंकि वह व्यापार सूचना संख्या 10/2018 में उल्लिखित मानदंडों को पूरा करने में विफल रहता है।
- घ. डीजीटीआर द्वारा जारी व्यापार सूचना सभी व्यापार सुधार ढांचों के लिए लागू है।
- ङ. आवेदकों ने द्विपक्षीय रक्षोपाय नियमावली के नियम 4(2)(ख) के तहत अपेक्षित समायोजन योजना नहीं दी है।
- च. तथाकथित वृद्धि सीमा शुल्कों में कमी अथवा उन्हें समाप्त करने के परिणामस्वरूप नहीं है, जैसा कि कोरिया-भारत सीईपीए के अनुच्छेद 2.22 के तहत अपेक्षित है।
- छ. रक्षोपाय संबंधी करारों के तहत "गंभीर क्षति" के मानक "बहुत अधिक" और "सख्त" हैं।
- ज. अनुच्छेद 4.2(क) में सूचीबद्ध सभी कारकों की क्षति के मूल्यांकन के लिए जांच की जानी होती है।
- झ. आवेदकों की वार्षिक रिपोर्टों के अनुसार, ऑर्थोक्सिलीन की कीमतों में अस्थिरता, रख-रखाव के लिए संयंत्र की बंदी आदि से भी उद्योग का निष्पादन प्रभावित हुआ है।
- ञ. जांच में कारणात्मक संपर्क का अभाव है। प्राधिकारी को कारणात्मक संपर्क की जांच करनी चाहिए तथा गैर-आरोपण विश्लेषण करना चाहिए।
- ट. आसियान देशों से आयातों में संबद्ध आयातों की तुलना में तीव्र वृद्धि हुई है। अतः अकेले गंभीर क्षति अकेले संबद्ध आयातों के कारण नहीं हो सकती।
- ठ. घरेलू उद्योग में घरेलू मांग को पूरा करने की क्षमता नहीं है। कोरिया गणराज्य से आयात मांग में वृद्धि से बढ़े हैं।
- ड. शुल्क लगाए जाने से आवेदक बाजार में अपने लिए प्रभावी स्थिति बना पाएंगे और नए प्रवेशकों के लिए अवरोध सृजित कर पाएंगे।
- ढ. सीईपीए के अनुच्छेद 2.22 तथा अर्जेंटीना फुटवियर एवं यूएस स्टील सेफगार्ड मामलों में डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय के निर्णय के अनुरूप "मात्राओं में ऐसा हाल, अचानक, तीव्र तथा काफी वृद्धि" नहीं है।
- ण. ऐसी कोई महत्वपूर्ण परिस्थितियां नहीं हैं जिनसे अनंतिम रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता हो।
- त. रक्षोपाय में क्षति की आवश्यकता अधिक है। घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति का पूर्णतः मूल्यांकन किया जाना है और डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय के अनुसार वे "न्यूनतम" होने चाहिए।
- थ. अग्रिम प्राधिकार योजना के तहत काफी आयात हो रहे हैं।
- द. अनुच्छेद 4.2(ख) में प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वे आयातों में वृद्धि के प्रभाव बांटें और कारणात्मक संपर्क दर्शाएं तथा गैर-आरोपण विश्लेषण सुनिश्चित करें।
- ध. याचिकाकर्ताओं द्वारा इस आरोप के विपरीत कि "उत्पाद की मांग में वृद्धि नहीं हुई है" मांग में सकारात्मक प्रवृत्ति है।
- न. आवेदकों द्वारा किए गए दावों के विरुद्ध अन्य देशों से आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है।
- प. बिक्री कीमत में वृद्धि पहुँच कीमत में वृद्धि से अधिक है।

घ.4 केमेक्सिल द्वारा किए गए अनुरोध (मूल रसायन, कॉस्मेटिक्स और डाइज निर्यात संबर्द्धन परिषद)

8. केमेक्सिल द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किया गया है:

शुल्क लगाए जाने से आयातित उत्पाद की कीमत में वृद्धि होगी जिससे स्थानीय उत्पादकों द्वारा कीमतों में वृद्धि होगी।

घ.5 गुजरात डाइस्टर्फ मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा किए गए अनुरोध

9. गुजरात डाइस्टर्फ मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. याचिका में सीईपीए की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए रक्षोपाय जांच की शुरुआत के लिए आधार सिद्ध करने हेतु कोई उपयुक्त साक्ष्य नहीं दिया गया है।
- ख. सीमा शुल्क में कमी अथवा समामि भी आयातों में वृद्धि का सुदूर कारण नहीं था और इस तर्क को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि घरेलू उद्योग को "गंभीर क्षति" हुई।
- ग. अन्य देशों से आयातों का प्रभाव और कोरिया, ताइवान तथा इजराइल पर पाटनरोधी शुल्क की समामि याचिका में स्पष्ट नहीं की गई है।
- घ. थाइलैंड और इंडोनेशिया तथा अन्य देशों, जिसके साथ भारत में एफटीए हस्ताक्षरित किए हैं, से कोरिया गणराज्य में तुलनीय स्तर पर आयातों में वृद्धि हुई है।
- ङ. कोरिया से आयातों की कीमत अन्य देशों से आयातों की कीमतों की तुलना में अधिक थी।
- च. याचिका में वार्षिक रिपोर्टों में प्रकटनों के अनुसार, उत्पादन में कटौती हुई है और मांग-आपूर्ति अंतराल को पूरा करने के लिए आयातों में वृद्धि आवश्यक हो गई थी।
- छ. टीसीएल के सीईओ ने अपने एक भाषण में उल्लेख किया है कि उत्पादन कम और लागत अधिक थी क्योंकि प्रमुख पुनरुद्धार परियोजना चल रही थी।
- ज. अगस्त, 2019 में आईजीपीएल की निवेशक प्रस्तुति के अनुसार, उच्च घरेलू मांग की आड़ में पिछले तीन वर्षों में आयातों में वृद्धि हुई है।
- झ. एशियन पेंट्स प्लांट की बंदी के प्रभाव से उत्पादन में गिरावट और आयातों में वृद्धि प्रभावित हुई है न कि सीमा शुल्क में कमी के कारण।
- ञ. याचिकाकर्ता उत्पादन और आपूर्ति करने में असमर्थ हैं क्योंकि ऑर्थोक्सिलीन के उत्पादन में धीमी वृद्धि है जिससे हो सकता है कि घरेलू उद्योग कच्ची सामग्री प्राप्त करने में कठिनाई का सामना कर रहा हो।
- ट. 25 जुलाई, 2019 को थिरूमलाई केमिकल्स लिमिटेड द्वारा प्रबंधन भाषण में वित्तीय वर्ष 2018-19 में निष्पादन के संबंध में उल्लेख किया गया था कि "वित्तीय वर्ष की पहली छमाही प्रत्येक मानदंड में उत्कृष्ट थी"। यह भी उल्लेख किया गया है कि निचले स्तर के उद्योगों में ग्राहकों ने स्टॉक न रखना शुरू कर दिया और कीमतें हताश बैंकों की स्वभाविक प्रतिक्रिया द्वारा और अधिक नीचे संचालित हुईं।
- ठ. आईजी पैट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के भाषण में यह कहा गया था कि "वर्ष 2018 अस्थिर कच्चे तेल की कीमतों से माना गया था जिनसे पीए के लिए भी कच्ची सामग्री की कीमतों में वृद्धि हुई।"
- ड. याचिका में प्रस्तुत क्षति संबंधी आंकड़े कोई "गंभीर क्षति" नहीं दर्शाते।
- ढ. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए मानी गई क्षति अवधि अप्रैल, 2015 से जून, 2019 तथा जांच की शुरुआत की अधिसूचना के अनुसार है, परंतु क्षति संबंधी आंकड़े इस अवधि के लिए उपलब्ध नहीं हैं।
- ण. याचिकाकर्ताओं ने सितंबर, 2017 की अवधि तक पाटन को क्षति का कारण होने का दावा किया है।
- त. नवीनतम तिमाही के लिए आंकड़े पूर्व वर्षों को तिमाही के समतुल्य में बदलने के बजाए वार्षिकीकृत किया जा सकता था जो कि उचित दृष्टिकोण ही है।
- थ. घरेलू उद्योग का उत्पादन क्योर ऑयल तथा अन्य पैट्रोकेमिकल उत्पादों में अस्थिरता सुदूर-पूर्व में मंदी, यूएस-चीन व्यापार प्रतिबंध आदि, मांग आदि को पूरा करने के लिए विस्तारों को पूरा करने में विलंब जैसे विभिन्न मुद्दों के बावजूद नवीनतम अवधि में 13 अंक तक बढ़ा है।
- द. 2007-08 की तुलना में नवीनतम अवधि तक घरेलू उद्योग की बिक्री भी 38 अंकों तक बढ़ी है जो यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई।

- ध. घरेलू उद्योग की क्षमता में 26 अंक तक वृद्धि हुई है। क्षमता में वृद्धि गंभीर क्षति का कारण है और इसे घरेलू उद्योग के क्षति संबंधी दावों को नकारने के कारक के रूप में देखा जाना चाहिए।
- न. घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई कीमत कटौती उद्भिन्न है क्योंकि वह खुद घरेलू उद्योग द्वारा लगाए गए अधिक एनएसआर के आधार पर हो सकती है।
- त. यदि इन वर्षों में मालसूची *** मी. टन की रेंज में रही तो वह अब क्षति नहीं दर्शाती।
- प. दिए गए आंकड़ों के अनुसार, 2018-19 की पहली तिमाही के बाद लाभप्रदता में गिरावट है। जब कोरिया, ताइवान और इजराइल से विचाराधीन उत्पादों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क रद्द किया गया था। लाभप्रदता मानदंड में गिरावट नहीं है बल्कि असामान्य रूप से उच्च लाभों में सुधार है।
- फ. कोरिया गणराज्य से आयातों में तथाकथित वृद्धि और दिए गए कारणों तथा दावा किए गए तर्क के बीच कोई कारणात्मक संपर्क नहीं है।
- ब. घरेलू उद्योग ने कोई समायोजन योजना प्रस्तुत नहीं की है।
- भ. द्विपक्षीय रक्षोपाय शुल्क का प्रयोजन जनता को लाभ प्रदान करना है, तथापि, चूंकि भारत में मांग-आपूर्ति अंतराल है, अतः वर्तमान जांच जनहित में नहीं है।

घ.5 केएलजे प्लास्टिसाइजर्स लि., पायल पॉलीप्लास्ट प्रा. लि., रचना प्लास्टिक्स और पीसीएल ऑयल एंड सॉल्वेंट्स लि. द्वारा किए गए अनुरोध

10. केएलजे प्लास्टिसाइजर्स लि., पायल पॉलीप्लास्ट प्रा. लि., रचना प्लास्टिक्स और पीसीएल ऑयल एंड सॉल्वेंट्स लि. द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - क. याचिकाकर्ता यह औचित्य बनाने के लिए साक्ष्य प्रदान करने में विफल रहे कि कोरिया गणराज्य से आयातों में वृद्धि सीमा शुल्कों में कमी के कारण है।
 - ख. थाइलैंड और इंडोनेशिया, जिनके साथ भारत ने एफटीए हस्ताक्षरित किए हैं, से आयातों में वृद्धि का घरेलू उद्योग पर प्रभाव स्पष्ट नहीं किया गया है। आयात ताइवान और इजराइल से भी बढ़े हैं।
 - ग. आयातों में वृद्धि पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति के कारण हो सकती है न कि सीमा शुल्कों में कमी के कारण। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग को शुल्क के समय भारी लाभ प्राप्त थे जो अब ठीक कर दिए गए हो सकते हैं।
 - घ. भारत में मांग-आपूर्ति अंतराल है जिससे भी आयातों में वृद्धि हो रही है।
 - ङ. घरेलू उद्योग के सामने उत्पादन क्षमताओं के पुनरुद्धार, ऑर्थोक्सिलीन की कीमतों में अस्थिरता, योजनागत क्षमता विस्तारों में विलंब, अल्पावधियों के लिए योजनागत बंदियों आदि के कारण संबद्ध सामानों की आपूर्ति में कठिनाइयां आ रही हैं।
 - च. आईजीपीएल के निवेशकों ने अगस्त, 2019 को एक प्रस्तुति में यह उल्लेख किया था कि "आयात पिछले तीन वर्षों में अत्यधिक घरेलू मांग की आड़ में बढ़े हैं।"
 - छ. घरेलू उद्योग मांग को पूरा करने में अक्षम है जिससे अन्य देशों से आयातों में वृद्धि हुई।
 - ज. इसके अतिरिक्त, आईजीपीएल के अनुसार, "पीए 2 संयंत्र की योजनागत बंदी थी क्योंकि उसमें उत्प्रेरक परिवर्तन अपेक्षित था।"
 - झ. टीसीएल के सीईओ ने अपने एक भाषण में उल्लेख किया है कि "भारत में चल रही प्रमुख पुनरुद्धार परियोजना से कम उत्पादन हुआ और अधिक लागत आई।"
 - ञ. जुलाई, 2017 में बंद हुए एशिया पेंट्स प्लांट ने भारत में पीएएन का उत्पादन प्रभावित किया।
 - ट. आवेदकों के सामने कच्ची सामग्री का मुद्दा रहा है तथा क्षमता पुनरुद्धार का भी मुद्दा था जिसने उत्पादन को प्रभावित किया हो सकता है।

- ठ. थिरूमलाई केमिकल्स लिमिटेड के संवर्धक द्वारा 25 जुलाई, 2019 को अपने भाषण में यह उल्लेख किया गया था कि वित्तीय वर्ष की पहली छमाही प्रत्येक मानदंड में उत्कृष्ट थी, परंतु बाद के महीनों में मंदी थी। निचले स्तर के उद्योगों में ग्राहकों ने स्टॉक न रखना आरंभ कर दिया और कीमतें और नीचे चली गईं।
- ड. आईजी पैट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के भाषण में यह उल्लेख था कि "वर्ष 2018 अस्थिर कच्चे तेल की कीमतों से माना गया था जिनसे पीए के लिए भी कच्ची सामग्री की कीमतों में वृद्धि हुई।"
- ढ. क्षति संबंधी आंकड़े कोई "गंभीर क्षति" नहीं दर्शाते तथा घरेलू उद्योग की स्थिति में कोई हानि नहीं हुई है।
- ण. याचिकाकर्ताओं को प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षति अवधि के लिए क्षति के आंकड़े देने के लिए निर्देश दिए जाने चाहिए क्योंकि याचिका में दिए गए आंकड़े प्राधिकारी द्वारा आंकड़ों की आवश्यकता को पूरा नहीं करते।
- त. याचिका में क्षति अवधि वही नहीं है जो महानिदेशक द्वारा निर्धारित की गई है, अतः क्षति की वास्तविक जांच संभव नहीं है।
- थ. कोरिया से आयात 2007-2019 से बढ़े। तथापि, अन्य देशों से आयात उसी समयावधि में अत्यधिक बढ़े जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आयात सभी देशों से बढ़े हैं और यह दावा कि कोरिया से आयात सीमा शुल्क की कमी के कारण बढ़े हैं, आधारहीन है।
- द. OX (ऑर्थोक्सिलीन) की आपूर्ति संबंधी कठिनाई के कारण घरेलू उद्योग का उत्पादन प्रभावित हुआ हो सकता है। साथ ही, क्योर ऑयल और अन्य पैट्रोकेमिकल उत्पादों में अस्थिरता सुदूर-पूर्व में मंदी, यूएस-चीन व्यापार प्रतिबंध आदि विस्तारों को पूरा करने में विलंब का योगदान रहा होगा।
- ध. घरेलू उद्योग ने गंभीर क्षति के अपने दावे का औचित्य नहीं दिया क्योंकि उसकी मात्रा और कीमत मानदंडों में वृद्धि है।
- न. निर्णायक जांच में कीमत कटौती 0-5 प्रतिशत सकारात्मक थी। तथापि, यह पाया गया था कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई। आयातों की पहुँच कीमत में स्पष्ट रूप से घरेलू उद्योग को अपने कीमतों कम करने के लिए मजबूर नहीं किया था और इसके विपरीत, एनएसआर बढ़ा।
- प. याचिकाकर्ता कोरिया से आयातों में तथाकथित वृद्धि तथा घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई क्षति के बीच कोई कारणात्मक संपर्क स्थापित नहीं कर पाए।
- फ. आवेदन पत्र में इस संबंध में ऐसी कोई समायोजन योजनाएं नहीं हैं कि आवेदक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा का सामना करने के लिए उत्पादकता में वृद्धि, लागत में कमी और बिक्री कीमतों में सुधार हासिल करने के लिए अपनी वर्तमान स्थिति में सुधार करने के लिए ऐसी योजना बना रहे हैं।
- ब. आयात का महत्वपूर्ण भाग मांग-आपूर्ति अंतराल को पूरा करने के लिए आवश्यक था और यदि कोई द्विपक्षीय शुल्क लगाया जाता है तो वह जनहित के विरुद्ध होगा।

घ. प्राधिकारी द्वारा जांच

11. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उनके अनुरोधों में उपलब्ध कराई गई सूचना पर प्राधिकारी द्वारा वर्तमान निर्धारण के प्रयोजन के लिए विचार किया गया है। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के विचारों की जांच की है और प्राथमिक जांच परिणामों के प्रयोजन के लिए उन पर उपयुक्त रूप से विचार किया है।
- क. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदन पत्र में अप्रैल, 2007 से जून, 2019 तक की अवधि के आंकड़े हैं। इसके अतिरिक्त, जांच की शुरुआत का उत्तर देते हुए आवेदकों ने सितंबर, 2019 तक की अवधि के लिए आंकड़े दिए हैं। इस प्रकार, हितबद्ध पक्षकारों के पास संगत सूचना है और अप्रैल, 2007 से सितंबर, 2019 तक की अवधि के लिए सूचना पर टिप्पणी करने का अवसर है। प्राधिकारी ने बढ़े हुए आयातों और घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति की जांच करने के प्रयोजन के लिए अप्रैल, 2015 से सितंबर, 2019 तक की अवधि मानी है। तथापि, चूंकि हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि प्राधिकारी को इस पर विचार करना अपेक्षित है कि क्या आयातों में वृद्धि करार के तहत शुल्क रियायतों का परिणाम है और परिणामस्वरूप क्षति पहुँचा रहे हैं, प्राधिकारी ने यह निर्धारित करने के लिए अप्रैल, 2007 से जून, 2019 तक की अवधि के लिए आवेदन पत्र में निहित सूचना पर विचार किया है कि

- क्या बढ़े हुए आयात प्रशुल्क रियायत का परिणाम हैं। जुलाई-सितंबर, 2019 तक की अवधि को भी यह विचार करते हुए जोड़ा गया है कि यह एक रक्षोपाय जांच है और प्राधिकारी ने बाद की अवधि, शुरुआत के बाद, जांच की अवधि के आंकड़े जोड़े हैं।
- ख. जहां तक समायोजन योजना का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि वह शुल्क की अवधि के लिए संगत है, न कि प्राथमिक निर्धारण के चरण पर, तथापि घरेलू उद्योग ने जांच की शुरुआत के बाद एक समायोजन योजना दी है।
- ग. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक प्रतिभागिता करार के साथ पठित भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक प्रतिभागिता करार (द्विपक्षीय रक्षोपाय) नियमावली, 2017 के तहत शुरू की गई एक द्विपक्षीय रक्षोपाय जांच है। प्राधिकारी ने इस बात की जांच की है कि क्या बढ़े हुए आयात करार के तहत प्रशुल्क रियायतों का परिणाम हैं। इस प्रयोजन के लिए प्राधिकारी ने अप्रैल, 2007 से सितंबर, 2019 तक उत्पाद के आयातों पर विचार किया है। यह देखा जाता है कि आयातों की मात्रा पूर्ण दृष्टि से और उत्पादन तथा खपत के संबंध में बढ़ी है क्योंकि प्रशुल्क रियायतें बढ़ी थीं।
- घ. जहां तक गैर-संबद्ध देशों से आयातों का संबंध है, यह देखा जाता है कि लागू सीमा शुल्कों को जोड़ने के बाद आयातों की पहुँच कीमत कोरिया से आयातों की पहुँच कीमत से तुलना करने पर गैर-संबद्ध देशों से अधिक है। यह सिद्ध करता है कि अन्य देशों से आयात घरेलू उद्योग को क्षति का प्राथमिक कारण नहीं है।
- ङ. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि आयात पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने के कारण बढ़े हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह इस बात को सिद्ध नहीं करता कि क्षति कोरिया से आयातों के कारण नहीं है। इसके अतिरिक्त, यह नोट किया जाता है कि कोरिया से कम से कम एक उत्पादक पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन नहीं था।
- च. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि आयात मांग-आपूर्ति अंतराल के कारण बढ़े हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मांग-आपूर्ति अंतराल ज्यादातर आयातों का औचित्य बना सकते हैं। तथापि, कोरिया से आयातों से पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से ही कम नहीं है बल्कि कई देशों से आयात कीमत से भी कम है। इसके अतिरिक्त, कई देश भारतीय बाजार में उत्पाद की आपूर्ति करते रहे हैं। तथापि, कोरिया से आयात का हिस्सा कोरियाई आयातों द्वारा प्राप्त प्रभावी स्थिति दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग ने संगत अवधि के दौरान उत्पादन और घरेलू बिक्री में गिरावट का सामना किया है। घरेलू उद्योग में मालसूची बढ़ी है। ये तथ्य यह नहीं दर्शाते कि बढ़े हुए आयात एशियन पेंट्स द्वारा उत्पादन बंद करने के कारण हैं।
- छ. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि अग्रिम प्राधिकार योजना के तहत काफी आयात हुए हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि आयात करार के तहत शून्य शुल्क के अंतर्गत हैं, अतः यह इस तर्क को नकारता है कि कोई हितबद्ध पक्षकार अग्रिम लाइसेंस के तहत आयात क्यों करेगा और अनावश्यक रूप से निर्यात दायित्व लेगा, जब शुल्क छूट की समान मात्रा कोई निर्यात दायित्व लिए बिना उपलब्ध है।
- ज. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक प्रतिभागिता करार (द्विपक्षीय रक्षोपाय) नियमावली, 2017 और भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक प्रतिभागिता करार के तहत है।
- झ. जहां तक याचिकाकर्ता कंपनियों की वार्षिक रिपोर्टों में विवरणों का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति व्यापक रूप से वर्तमान वर्ष में हुई है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता कंपनियों के प्रकाशित लेखापरीक्षित न किए गए तिमाही परिणाम भी लाभ में काफी गिरावट दर्शाते हैं।
- ञ. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह सिद्ध नहीं किया गया है कि क्षमता पुनरुद्धार, योजनागत क्षमता विस्तारों में विलंब, योजनागत अल्पावधि बंदी आदि कैसे घरेलू उद्योग को क्षति का प्रमुख कारण हो सकते हैं जबकि वर्तमान आंकड़ों में विश्वास की गई सूचना में इनके निमित्त कोई लागत शामिल नहीं है।
- ट. जहां तक कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता का संबंध है, वह एक वैश्विक कारक है न कि भारतीय बाजार के लिए विशिष्ट।
- ठ. जहां तक क्षमता विस्तार का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि लाभ तथा निवेश पर आय के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में वर्तमान अवधि में तेजी से गिरावट आई जबकि कोई क्षमता अभिवृद्धि नहीं थी।

- ड. जहां तक निर्णायक समीक्षा के अंतिम जांच परिणामों के संदर्भ का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि निर्णायक समीक्षा जांच परिणाम अप्रैल, 2016 से सितंबर, 2017 जांच की अवधि के आधार पर हैं जबकि वर्तमान मामले में क्षति सर्वाधिक हाल की अवधि और जांच की अवधि के काफी बाद निर्णायक समीक्षा में जांच की गई अवधि में अधिक है।
- ढ. यह भी नोट किया जाता है कि प्रस्तावित उपाय केवल कोरिया से आयातों तक ही सीमित होंगे। अन्य सभी देशों से आयात बिना किसी रक्षोपाय के किए जाते रहेंगे। इस प्रकार, आपूर्ति का स्रोत प्रस्तावित उपाय के परिणामस्वरूप समाप्त नहीं होगा।

ड.1 विचाराधीन उत्पाद

12. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद प्रशुल्क शीर्ष 29173500 के तहत आने वाला "फ्थैलिक एनहाइड्राइड" (जिसे पीएएन भी कहा जाता है) एक फ्थैलिक एसिड का एनहाइड्राइड है और ऑर्थोक्सिलीन अथवा नैफ्थालीन के उत्प्रेरक ऑक्सीकरण द्वारा वाणिज्यिक रूप से उत्पादित किया जाता है।
13. पीएएन एक रंगहीन ठोस है, जिसे फ्थैलिक एनहाइड्राइड फ्लैक्स, फ्थैलिक एनहाइड्राइड (98 प्रतिशत मिन.), फ्थैलिक एसिड एनहाइड्रस, फ्थैलिक एनहाइड्राइड (99.8 प्रतिशत मिन.), आदि कहा जाता है। फ्थैलिक एनहाइड्राइड का उपयोग फ्थैलिक ईस्टर का उत्पादन करने के लिए किया जाता है जो प्लास्टिसाइजर के रूप में कार्य करता है। यह प्लास्टिक उद्योग में एक महत्वपूर्ण रासायनिक मध्यवर्ती है।

ड.2 घरेलू उद्योग

14. नियम 2(ख) द्विपक्षीय रक्षोपाय नियमावली, 2007 में निम्नलिखित उल्लेख है:

"घरेलू उद्योग" का अभिप्राय-

- (i) भारत के सीमा क्षेत्र में प्रचालित होने वाले समान अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्द्धी सामानों के समग्र रूप से उत्पादक; अथवा
- (ii) वे उत्पादक जिनका समान अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्द्धी सामानों के सामूहिक उत्पादन में उन सामानों के कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख अनुपात हो;

15. वर्तमान आवेदन पत्र मैसर्स आईजी पैट्रोकेमिकल्स लि. और मैसर्स थिरूमलाई केमिकल्स लि. द्वारा दायर किया गया है। एसआई ग्रुप प्रा. लि. इस समय भारत में इस उत्पाद का एकमात्र अन्य ज्ञात उत्पादक है। एसआई ग्रुप प्रा. लि. ने जांच की शुरुआत के बाद निर्धारित प्रपत्र में सूचना दायर की, परंतु समय सीमा की समाप्ति के बाद दायर की। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की क्षति के संबंध में आवेदकों अथवा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं। आवेदकों का उत्पादन में कुल भारतीय उत्पादन में प्रमुख हिस्सा है। अतः नियमावली के अनुसार आवेदन पत्र आधार की अपेक्षा को पूरा करता है। इस प्रकार, आईजी पैट्रोकेमिकल्स लिमिटेड और मैसर्स थिरूमलाई केमिकल्स लिमिटेड वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग हैं।

ड.3 जांच की अवधि

16. जांच की शुरुआत की सूचना में अधिसूचित किए गए अनुसार, वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए मानी गई अवधि अप्रैल, 2015 से जून, 2019 है। इसके अतिरिक्त, चूंकि यह एक रक्षोपाय जांच है, अतः विगत परिपाटी को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने सबसे हाल की अवधि, जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं, होने के नाते सितंबर, 2019 तक की अवधि के लिए आंकड़ों पर विचार किया है।

ड.4 गोपनीयता

17. नियमावली का नियम 6 सूचना की गोपनीयता से संबंधित है। गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक हुआ, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और इस सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं। प्राधिकारी ने सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया।

ड.5 व्यापक आर्थिक प्रतिभागिता करार के तहत सीमा शुल्क

18. व्यापक आर्थिक प्रतिभागिता करार (सीईपीए) के तहत रियायतों को ध्यान में रखते हुए फ़ैलिक एनहाइडाइड के आयातों पर सीमा शुल्क की दर निम्नलिखित थी:

सीमा शुल्क दर			
31 दिसंबर, 2009	10.94%	2010-11	10.55%
31 दिसंबर, 2010	9.38%	2011-12	8.99%
31 दिसंबर, 2011	7.81%	2012-13	7.42%
31 दिसंबर, 2012	6.25%	2013-14	5.86%
31 दिसंबर, 2013	4.69%	2014-15	4.30%
31 दिसंबर, 2014	3.13%	2015-16	2.74%
31 दिसंबर, 2015	1.56%	2016-17	1.17%
31 दिसंबर, 2016	0.00%	2017-18	0.00%
31 दिसंबर, 2017	0.00%	2018-19	0.00%
31 दिसंबर, 2018	0.00%		

ड.6 सूचना का स्रोत

19. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से संबद्ध सामानों के आयातों के ब्यौरों की व्यवस्था के लिए अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी ने अपेक्षित विश्लेषण के लिए आयातों की मात्रा एवं मूल्य के परिकलन के लिए डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर विश्वास किया है।

ड.7 कोरिया गणराज्य से बढ़े हुए आयात

20. भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक प्रतिभागिता करार (द्विपक्षीय रक्षोपाय) नियमावली, 2017 के नियम 2(ग) में उल्लेख है:

"बढ़े हुए आयातों" में कोरिया गणराज्य से आयातों में वृद्धि शामिल है, भले ही पूर्ण संदर्भ में हों अथवा घरेलू उत्पादन के संबंध में;

21. उपर्युक्त नियमावली में यह जांच अपेक्षित है कि क्या विचाराधीन उत्पाद के आयात पूर्ण दृष्टि से अथवा सापेक्ष दृष्टि से इतनी मात्राओं में बढ़े कि वे "बढ़े हुए आयात" बने। उपर्युक्त नियमावली में पूर्ण दृष्टि से और भारत में आयातों के संबंध में, भारत में उत्पादन एवं खपत के संबंध में आयातों का विश्लेषण अपेक्षित है। विचाराधीन उत्पाद के बढ़े हुए आयातों का विश्लेषण उपर्युक्त नियमावली को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

i. कोरिया गणराज्य से पूर्ण दृष्टि के आयात

22. आयातों का संचलन निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

क्रम सं.	वर्ष	आयात मात्रा	प्रवृत्ति	सीमा शुल्क
		मी. टन	सूचकांक	
1	2015-16	25,252	100	2.74%
2	2016-17	36,822	146	1.17%
3	2017-18	41,664	165	0.00%
4	2018-19	49,081	194	0.00%
5	अप्रैल, 19 – जून, 19	22,819	181	0.00%
6	जुलाई, 19 – सितंबर, 19	26,007	206	0.00%
7	अप्रैल से सितंबर, 19	48,826	193	0.00%

23. यह देखा जाता है कि विचाराधीन उत्पाद के आयात इस अवधि में पूर्ण दृष्टि से काफी बढ़े हैं।

ii. **भारत में सकल आयातों के संबंध में आयात**

24. कोरिया गणराज्य और अन्य देशों से संबद्ध सामानों के आयातों का हिस्सा निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

क्रम सं.	वर्ष	आयात मी. टन में			आयातों में हिस्सा	
		कोरिया गणराज्य	अन्य देश	कुल आयात	कोरिया गणराज्य	अन्य देश
1	2015-16	25,252	53,866	79,118	32%	68%
2	2016-17	36,822	63,115	99,937	37%	63%
3	2017-18	41,664	88,775	1,30,439	32%	68%
4	2018-19	49,081	95,579	1,44,660	34%	66%
5	अप्रैल, 19 – जून, 19	22,819	23,384	46,204	49%	51%
6	जुलाई, 19 – सितंबर, 19	26,007	23,830	49,837	52%	48%
7	अप्रैल से सितंबर, 19	48,826	47,214	96,041	51%	49%

25. यह देखा जाता है कि कोरिया से विचाराधीन उत्पाद के आयातों का हिस्सा बढ़ती हुई प्रशुल्क रियायत से इस अवधि में बढ़ा जबकि अन्य देशों के हिस्से में गिरावट आई। कोरियाई आयातों का अब शुल्क रियायत पूर्ण मात्रा तक बढ़ने से भारी हिस्सा है। यहां तक कि जब कई अन्य देशों से आयात सूचित किए जा रहे हैं तो सामूहिक रूप से उनका हिस्सा अकेले कोरिया के हिस्से से कम है।

iii. **भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में आयातों में वृद्धि**

26. भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में संबद्ध सामानों के आयातों का संचलन निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

	वर्ष	कोरिया आयात	भारतीय उत्पादन	मांग	के संबंध में आयात	
					उत्पादन	खपत
		मी .टन	प्रवृत्ति मी .टन	मी .टन	%	%
1	2015-16	25,252	100	3,32,413	8%	8%
2	2016-17	36,822	97	3,47,995	12%	11%
3	2017-18	41,664	100	3,72,030	14%	11%
4	2018-19	49,081	97	3,82,583	18%	13%
5	अप्रैल ,19 – जून ,19	22,819	91	97,163	35%	23%
6	जुलाई ,19 – सितंबर ,19	26,007	87	1,05,209	42%	25%
7	अप्रैल से सितंबर ,19	48,826	112	2,02,372	38%	24%

27. यह देखा जाता है कि कोरिया से आयात शुल्क रियायत में वृद्धि से भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में काफी बढ़े।

ड.8 क्षति

28. गंभीर क्षति नियमावली के तहत निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

(च) गंभीर क्षति का अर्थ किसी घरेलू उद्योग की स्थिति में काफी समग्र हानि है; और

(छ) "गंभीर क्षति के खतरे" का अर्थ है कि वह गंभीर क्षति जो तथ्यों के आधार पर न कि केवल आरोप, अनुमान अथवा सुदूर संभावना पर स्पष्ट रूप से आसन्न हो; और

29. इस प्रकार, आयातों में वृद्धि वह होनी चाहिए जो घरेलू उद्योग की स्थिति में काफी समग्र हानि करें।

30. नियमावली के नियम 7 में भी निम्नलिखित प्रावधान है:

प्राधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति का खतरा निर्धारित करेंगे, यथा:-

(क) प्राधिकारी पूर्ण दृष्टि से और सापेक्ष दृष्टि से मूल देश के सामान के आयातों में वृद्धि की दर तथा मात्रा, मूल के सामान के बड़े हुए आयातों द्वारा लिए गए घरेलू बाजार के हिस्से, बिक्री, उत्पादन, उत्पादकता, क्षमता उपयोग, लाभ और हानि तथा रोजगार के स्तर में परिवर्तन को विशेष रूप से उस उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले वस्तुपरक एवं मात्रात्मक सभी संगत कारकों का मूल्यांकन करेंगे; और

(ख) इस नियम के तहत निर्धारण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक जांच वस्तुपरक साक्ष्य के आधार पर मूल देश के सामान के बड़े हुए आयातों तथा उसकी गंभीर क्षति अथवा खतरे के बीच कारणात्मक संपर्क की मौजूदगी न दर्शाए और जब मूल देश के सामान के बड़े हुए आयातों को छोड़कर कोई अन्य कारक साथ ही घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा रहे हों तो वह क्षति मूल देश के सामानों के बड़े हुए आयातों के कारण नहीं होगी।

31. यह नोट किया जाता है कि सूचीबद्ध मानदंडों का मूल्यांकन विभिन्न उद्योगों और स्थितियों की विशेषताओं को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अतः प्राधिकारी ने वर्तमान मामले के तथ्यों और उद्योग की स्थिति को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति की जांच की है। इस प्रकार, सभी सूचीबद्ध कारकों और किन्हीं अन्य संगत कारकों की तकनीकी जांच के अलावा, यह अनिवार्य है कि उस उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत कारकों के आलोक में उद्योग की समग्र स्थिति का मूल्यांकन किया जाए। तदनुसार, गंभीर क्षति का विश्लेषण करने में सभी कारकों, जो नियमों में उल्लिखित हैं तथा अन्य कारकों जो गंभीर क्षति के निर्धारण के लिए संगत हैं, पर विचार किया गया है। गंभीर क्षति का निर्धारण उस उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत कारकों के आलोक में घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति के मूल्यांकन पर आधारित है।

क. पूर्ण एवं सापेक्ष दृष्टि से आयातों में वृद्धि

32. यह देखा जाता है कि संबद्ध सामानों के आयातों में पूर्ण दृष्टि से तथा भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में काफी वृद्धि हुई है। यह भी देखा जाता है कि आयात कोरियाई आयातों को दी गई पूर्ण रियायतों से काफी बड़े।

ख. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री

33. क्षमता, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

क्रम सं.	वर्ष	क्षमता	उत्पादन	क्षमता उपयोग	घरेलू बिक्री	निर्यात बिक्री	कोरिया गणराज्य आयात
		मी .टन	प्रवृत्ति मी .टन	%	मी .टन	प्रवृत्ति मी .टन	मी .टन
1	2015-16	3,06,110	100	89%	2,18,825	100	25,252
2	2016-17	3,06,110	97	86%	2,14,580	103	36,822
3	2017-18	3,06,110	100	89%	2,24,112	98	41,664
4	2018-19	3,06,110	97	87%	2,27,235	63	49,081

5	अप्रैल ,19 – जून ,19	76,528	91	82%	48,465	70	22,819
6	जुलाई ,19 – सितंबर ,19	76,528	87	78%	52,738	92	26,007
7	अप्रैल से सितंबर ,19	1,53,055	112	80%	1,01,203	81	48,826

34. यह देखा जाता है कि

क. घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में इस अवधि में गिरावट आई है।

ख. जबकि घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री 2018-19 तक बढ़ रही थी तो उसमें काफी गिरावट आई है।

ग. निर्यात में 2018-19 में गिरावट आई है और उसके बाद वृद्धि हुई। तथापि, निर्यातों की लाभप्रदता घरेलू बिक्री की तुलना में प्रतिकूल है।

ग. **घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा**

35. बाजार हिस्से का संचलन निम्नलिखित था:

क्रम सं.	वर्ष	घरेलू उद्योग	कोरियाई आयात	अन्य उत्पादक	अन्य देश	कुल
1	2015-16	66%	8%	10%	16%	100%
2	2016-17	62%	11%	10%	18%	100%
3	2017-18	60%	11%	5%	24%	100%
4	2018-19	59%	13%	3%	25%	100%
5	अप्रैल, 19 – जून, 19	50%	23%	3%	24%	100%
6	जुलाई, 19 – सितंबर, 19	50%	25%	3%	23%	100%
7	अप्रैल से सितंबर, 19	50%	24%	3%	23%	100%

36. यह देखा जाता है कि जबकि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई, तो कोरियाई आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई। समग्र आधार पर, जबकि घरेलू उद्योग ने इस अवधि में 16 प्रतिशत बाजार हिस्सा खोया तो कोरियाई आयातों में लगभग उसी स्तर तक बाजार हिस्सा प्राप्त किया।

घ. **रोजगार एवं उत्पादकता**

37. रोजगार एवं उत्पादकता संबंधी आंकड़े निम्नलिखित हैं:

क्रम सं.	वर्ष	कर्मचारियों की संख्या	प्रति दिन उत्पादकता	प्रति कर्मचारी उत्पादकता
		प्रवृत्ति सं.	प्रवृत्ति मी. टन/दिन	प्रवृत्ति मी. टन/सं.
1	2015-16	100	100	100
2	2016-17	100	97	97
3	2017-18	101	100	99
4	2018-19	103	97	95
5	अप्रैल, 19 – जून, 19	103	92	89
6	जुलाई, 19 – सितंबर, 19	103	87	85
7	अप्रैल से सितंबर, 19	103	89	87

38. प्रति दिन उत्पादकता और प्रति कर्मचारी उत्पादकता में हाल के वर्षों में गिरावट देखी गई। तथापि, आवेदकों ने अनुरोध किया कि इन कारणों के निष्पादन कई अन्य मानदंडों पर निर्भर हैं और आयातों से सीधे ही जुड़े हुए नहीं हैं।

ड. मालसूची

39. मालसूची संबंधी आंकड़े निम्नलिखित दर्शाते हैं:

क्रम सं.	विवरण	प्रवृत्ति औसत स्टॉक (मी. टन)
1	2015-16	100
2	2016-17	121
3	2017-18	72
4	2018-19	71
5	तिमाही-1-2019-20	140
6	तिमाही-2-2019-20	132

40. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग में मालसूची का स्तर इस अवधि में बढ़ा।

च. लाभ/हानि

41. लाभ तथा नियोजित पूंजी पर आय संबंधी आंकड़े निम्नलिखित दर्शाते हैं:

	वर्ष	लाभ/(हानि)		आरओआई
		प्रवृत्ति लाख रु.	प्रवृत्ति रु./मी. टन	प्रवृत्ति
1	2015-16	100	100	100
2	2016-17	285	291	205
3	2017-18	584	570	295
4	2018-19	407	392	216
5	अप्रैल, 19 – जून, 19	104	467	53
6	जुलाई, 19 – सितंबर, 19	-13	-54	5
7	अप्रैल से सितंबर, 19	45	98	32

42. यह देखा जाता है कि लाभ तथा नियोजित पूंजी पर आय में 2017-18 के बाद तेजी से ह्रास हुआ है। घरेलू उद्योग को जुलाई से सितंबर, 2019 की सबसे हाल की अवधि में वित्तीय हानियां हुई हैं।

छ. कीमत कटौती

43. प्राधिकारी ने इस बात की जांच की कि क्या कोरिया से आयात बाजार में उत्पाद की कीमतें निर्धारित कर रहे थे। इस प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने कोरिया से आयातों की पहुँच कीमत तथा घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से विभिन्न देशों से आयातों की पहुँच कीमत की तुलना की।

क्रम सं.	वर्ष	एनएसआर	पहुँच कीमत	कीमत कटौती	कीमत कटौती
		प्रवृत्ति रु./मी. टन	रु./मी. टन	रु./मी. टन	%
1	2015-16	100	56,387	*****	0-10%
2	2016-17	113	60,274	*****	5-15%
3	2017-18	119	66,989	*****	0-10%
4	2018-19	135	74,225	*****	0-10%
5	अप्रैल, 19 – जून, 19	126	68,900	*****	5-15%
6	जुलाई, 19 – सितंबर, 19	112	63,618	*****	0-10%
7	अप्रैल से सितंबर, 19	119	66,086	*****	0-10%

44. यह देखा जाता है कि आयातों की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम रही है। इस प्रकार, आयात घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती कर रहे थे।

45. प्राधिकारी ने कोरिया से आयातों की पहुँच कीमत के साथ घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, बिक्री कीमत में प्रवृत्तियों की जांच की। यह देखा जाता है कि क्योंकि आयातों की पहुँच कीमत पूर्व में बिक्री लागत से अधिक थी तो हाल की अवधि में आयातों की पहुँच कीमत बिक्री लागत से कम है। यदि घरेलू उद्योग ने इन आयात कीमतों पर बिक्री की होती तो वर्तमान अवधि में उसे हानियां हुई होतीं।

क्रम सं.	वर्ष	बिक्री की लागत	बिक्री कीमत	पहुँच कीमत
		प्रवृत्ति रु./मी. टन	प्रवृत्ति रु./मी. टन	रु./मी. टन
1	2015-16	100	100	56,387
2	2016-17	105	113	60,274
3	2017-18	99	119	66,989
4	2018-19	123	135	74,225
5	अप्रैल, 19 – जून, 19	127	126	68,900
6	जुलाई, 19 – सितंबर, 19	118	112	63,618
7	अप्रैल से सितंबर, 19	122	119	66,086

ड. निष्कर्ष

46. यह अनंतिम रूप से निष्कर्ष निकाला जाता है कि विचाराधीन उत्पाद के आयातों में पूर्ण दृष्टि से तथा भारत में सकल आयातों के संबंध में, भारतीय उत्पादन और खपत के संबंध में काफी वृद्धि हुई है। कोरिया गणराज्य के आयातों में काफी उछाल के परिणामस्वरूप घरेलू उत्पादक को उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग, बाजार हिस्सा, लाभ, निवेश पर आय में गिरावट तथा बढ़ते हुए कम लाभप्रद निर्यातों और बढ़ती हुई मालसूची के संदर्भ में गंभीर क्षति हुई है। विभिन्न मानदंडों के संबंध में, घरेलू उत्पादक के निष्पादन पर विचार करते हुए, यह आगे की जांच होने तक अनंतिम रूप से निष्कर्ष निकाला जाता है कि घरेलू उद्योग को कोरियाई आयातों को दी गई शुल्क रियायतों के परिणामस्वरूप गंभीर क्षति हुई है जिससे कोरिया से कम कीमतों पर विचाराधीन उत्पाद के आयात बढ़े।

च. गंभीर क्षति का खतरा

47. नियमावली में निम्नलिखित प्रावधान है:

"गंभीर क्षति का खतरा" का अर्थ है गंभीर क्षति जो स्पष्ट रूप से आसन्न हो और तथ्यों के आधार पर निर्धारित की जाएगी न कि केवल आरोप, अनुमान अथवा सुदूर संभावना पर;

48. यह नोट किया जाता है कि कोरिया से संबद्ध आयात पूर्ण दृष्टि से तथा भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में काफी बड़ी हुई मात्राओं में भारतीय बाजार में आ रहे हैं। घरेलू उद्योग की क्षमता का उपयोग कम हुआ था और कोरिया से बड़े हुए आयातों ने स्थिति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। संबद्ध सामानों के आयातों की पहुँच कीमत, कोरिया में उनकी निर्यातानुमुखता के साथ भारी क्षमताओं के बीच अंतर को ध्यान में रखते हुए यह सिद्ध है कि कोरिया से संबद्ध सामान कीमत आकर्षक रहने की संभावना है जो घरेलू उद्योग को क्षति का न्यूनतम खतरा पैदा कर रहे हैं। गंभीर क्षति का खतरा निम्नलिखित कारकों से सिद्ध है:

क. घरेलू और आयातित उत्पाद के बीच कीमत अंतर से कोरिया से संबद्ध सामानों के आयातों में वृद्धि हुई है।

ख. कोरिया के उत्पादकों के पास काफी अनुपयुक्त क्षमताएं हैं, जैसा कि कोरियाई उत्पादकों द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर से सिद्ध है। परिणामस्वरूप, कोरिया के उत्पादक निरंतर अतिरिक्त बाजारों की तलाश कर रहे हैं।

ग. भारत में कोरिया से निर्यातों में वृद्धि है और शेष विश्व को निर्यातों में गिरावट है।

घ. उत्पाद की मांग बढ़ रही है और भारतीय बाजार व्यापक और कीमत संवेदी है।

49. उपर्युक्त के मद्देनजर, अंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि कोरिया से संबद्ध सामानों के बड़े हुए आयातों से घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग कोरिया से आयातों से गंभीर क्षति के निरंतर खतरे का सामना कर रहा है।

छ. कारणात्मक संपर्क

50. ऊपर दिए गए अनुसार घरेलू उद्योग के निष्पादन का व्यापक मूल्यांकन यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है और कोरिया से बड़े हुए आयातों से और भी गंभीर क्षति का खतरा है। प्राधिकारी ने इस बात की जांच की कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति शुल्क रियायतों तथा परिणामस्वरूप कोरिया से आयातों में वृद्धि के कारण है। इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकारों के इन तर्कों के मद्देनजर कि प्राधिकारी को इस बात की जांच करना अपेक्षित है कि क्या दावा की गई क्षति शुल्क रियायतों के कारण है अथवा किन्हीं अन्य कारकों से है, प्राधिकारी ने उस अवधि सहित मंदी अवधि में घरेलू उद्योग के निष्पादन पर भी विचार किया जब शुल्क रियायत नहीं थी। इस निमित्त संगत सूचना घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन पत्र में निहित है जिसे हितबद्ध पक्षकार आवेदन पत्र तथा अनुरोधों के अगोपनीय रूपांतर के माध्यम से देख सकते हैं।

क. प्राधिकारी ने यह जांच कि क्या किसी अन्य कारक से घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है। प्राधिकारी ने विभिन्न जांच मानदंडों और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए मानदंडों पर विचार किया और निष्कर्ष निकाला कि घरेलू उद्योग को सूचित क्षति इस समय प्रचालित हो रहे अन्य कारकों की संभावित मौजूदगी के कारण नहीं है।

ख. कोरिया से उत्पाद के आयातों में कोरियाई आयातों को प्रशुल्क रियायतों में वृद्धि तथा उसके सीमा शुल्क की समामि से काफी वृद्धि हुई है।

ग. पूरी शुल्क रियायतों से कोरियाई आयातों की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है। कोरियाई कीमतें ही बाजार में उत्पाद की कीमतों का निर्धारण कर रही थीं।

घ. घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग इष्टतम स्तर से कम है और परिणामस्वरूप उत्पादन में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग के उत्पादन और घरेलू बिक्री में हाल की अवधि में शुल्क रियायतों के परिणामस्वरूप बढ़ते हुए आयातों से गिरावट आई है। घरेलू बिक्री में गिरावट और बढ़ती हुई मालसूची भारत में आयातों में वृद्धि का परिणाम है।

51. इस प्रकार यह सिद्ध है कि घरेलू उद्योग को क्षति बढ़े हुए आयातों के कारण हुई है और कोरिया से संबद्ध सामानों के बढ़े हुए आयातों और कोरियाई आयातों को दी गई शुल्क रियायतों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति तथा गंभीर क्षति के खतरे के बीच कारणात्मक संपर्क है।

ज. महत्वपूर्ण परिस्थिति

52. द्विपक्षीय रक्षोपाय नियमावली के नियम 8 में यह प्रावधान है कि प्राधिकारी शीघ्रता से जांच करेंगे और महत्वपूर्ण परिस्थितियों में जहां यह स्पष्ट साक्ष्य हो कि बढ़े हुए आयातों से घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है अथवा वे गंभीर क्षति पैदा करने का खतरा पैदा कर रहे हैं और जहां अनंतिम द्विपक्षीय रक्षोपाय लगाने में विलंब घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाएगा जो ठीक करना कठिन होगा, प्राधिकारी मूल देश के सामान के बढ़े हुए आयातों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति के खतरे के संबंध में प्राथमिक जांच परिणाम रिकार्ड करें। प्राधिकारी मानते हैं कि निम्नलिखित तथ्य अंतरिम रक्षोपाय लगाए जाने की आवश्यकता वाली महत्वपूर्ण परिस्थितियों की मौजूदगी सिद्ध करते हैं:

- क. 2017-18 में पूरी सीमा तक बढ़ती हुई शुल्क रियायतों से उत्पाद के आयात 2017-18 में 32 प्रतिशत और 2018-19 में 34 प्रतिशत और अप्रैल, 2019-जून, 2019 तक 49 प्रतिशत तक बढ़े तथा उसके बाद उच्च स्तरों पर बने रहे हैं।
- ख. वर्तमान अवधि के दौरान काफी शुल्क रियायतों से घरेलू उद्योग के लाभों में काफी गिरावट आई है और 2019-20 की दूसरी तिमाही में हानियों में चले गए।
- ग. घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में उत्पाद की घरेलू मांग में वृद्धि के बावजूद गिरावट आई है।
- घ. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में काफी गिरावट आई है।
- ङ. परिणामस्वरूप, घरेलू उत्पादक की घरेलू बिक्री में सबसे हाल की अवधि (अप्रैल-सितंबर, 2019 की अवधि) में काफी गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता भी इस अवधि में काफी प्रभावित हुई है और 2019-20 की दूसरी तिमाही में हानियां हुईं। अप्रैल से सितंबर, 2019 में बिक्री की मात्रा 2015-16 में बेची गई मात्रा से 8 प्रतिशत कम थी।
- च. घरेलू उद्योग घरेलू बिक्री कीमत से कम कीमत पर संबद्ध सामानों का निर्यात करने के लिए मजबूर हो गया है।

53. यह नोट किया जाता है कि प्रस्तुत कारक महत्वपूर्ण परिस्थितियां हैं और घरेलू उद्योग के समग्र निष्पादन को प्रभावित कर रहे हैं जो अनंतिम द्विपक्षीय रक्षोपाय लगाए जाने का औचित्य बनाते हैं।

झ. समायोजन योजना

54. आवेदकों ने जांच प्रक्रिया के दौरान समायोजन योजनाओं के ब्यौरे दिए हैं। घरेलू उद्योग ने बताया है कि वह कई कारणों से लागतें कम करने के निमित्त निर्देशित उपाय करेंगे। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि वे लागतें कम करने के उपाय कर रहे हैं। आईजी पैट्रोकेमिकल्स ने समायोजन योजना दी है जिसमें मौजूदा उत्प्रेरक को बदलकर कच्ची सामग्री लागत में कमी करने संबंधी कार्रवाई योजना, वसूलियों में सुधार, विद्युत एवं ईंधन लागत में कमी, क्षमता अभिवृद्धि तथा मौजूदा संयंत्रों की यूटिलिटीयों को एकीकृत करने, प्रशासनिक खर्चों, कार्मिक लागत और वित्तीय लागत के निमित्त लागतों को कम करने के प्रयास शामिल हैं। थिरूमलाई केमिकल्स ने एक समायोजन योजना दी है जिसमें उच्चतम क्षमता तथा दक्षता के लिए उपस्करों का उन्नयन कर लागत में कमी, उत्पादन में सुधार, ऊर्जा लागतों में कमी, तेल खपत में कमी, वेतन एवं मजदूरियों, भंडार तथा अतिरिक्त हिस्से-पुर्जों, मरम्मत एवं रख-रखाव तथा प्रशासनिक ऊपरी खर्चों में कमी शामिल है। प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदकों ने कोरियाई आयातों की तुलना में प्रतिस्पर्द्धी बनने के लिए एक समायोजन योजना तैयार की है।

ज. निष्कर्ष एवं सिफारिश

55. उपर्युक्त प्राथमिक निर्धारण के आधार पर अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि संबद्ध सामानों के बढ़े हुए आयातों से घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति तथा गंभीर क्षति का खतरा भी हुआ है। यह माना जाता है कि महत्वपूर्ण परिस्थितियां विद्यमान हैं जहां रक्षोपाय लगाने में विलंब से घरेलू उत्पादकों को अपूरणीय क्षति होगी। द्विपक्षीय रक्षोपाय लगाए जाने के संबंध में भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक प्रतिभागिता करार (द्विपक्षीय रक्षोपाय) नियमावली, 2017 के नियम 9 में निम्नलिखित उल्लेख है:

(1) प्राधिकारी के प्राथमिक जांच परिणामों के आधार पर केंद्र सरकार-

(क) व्यापार करार के तहत किए गए प्रावधान के अनुसार मूल देश के सामान पर सीमा शुल्क की किसी दर को और कम करने को रद्द कर सकती है; अथवा

(ख) निम्नलिखित से कमतर से अनधिक के स्तर तक मूल देश के सामान पर सीमा शुल्क की दर बढ़ा सकती है:

(i) सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र में उस समय प्रभाव में मूल देश के सामान पर सीमा शुल्क की दर लागू की हो जब द्विपक्षीय रक्षोपाय किया गया हो; और

(ii) सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र में व्यापार करार की लागू प्रविष्ट तारीख से तत्काल पूर्व के दिवस को प्रभाव में मूल देश के सामान पर सीमा शुल्क की दर लागू की हो।

(2) उप नियम (1) के तहत द्विपक्षीय रक्षोपाय उन्हें लगाए जाने की तारीख से 200 दिनों से अनधिक की अवधि के लिए ही लागू रहेंगे।

56. उपर्युक्त की जांच करने के बाद, भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक प्रतिभागिता करार (द्विपक्षीय रक्षोपाय) नियमावली, 2017 के नियम 9 के अनुसार, अनंतिम द्विपक्षीय रक्षोपाय की सिफारिश करना उपर्युक्त माना जाता है। तदनुसार, अंतिम निर्धारण होने तक प्राधिकारी अनंतिम रूप से कोरिया गणराज्य के मूल के संबद्ध सामानों के आयातों पर सीमा शुल्क की दर द्विपक्षीय रक्षोपाय लागू होने की तारीख को संबद्ध सामानों पर एमएफएन शुल्क के स्तर तक अथवा व्यापार करार के लागू होने की तारीख से तत्काल पूर्व के दिवस को संबद्ध सामानों पर एमएफएन शुल्क, जो भी कम हो, बढ़ाने की सिफारिश करते हैं।

57. उपर्युक्तानुसार, उपर्युक्त उत्पाद के आयात पर अनंतिम द्विपक्षीय रक्षोपाय की 200 (दो सौ दिन) दिनों की अवधि के लिए सिफारिश की जाती है।

ट. आगे की प्रक्रिया

58. प्राथमिक जांच परिणाम अधिसूचित करने के बाद निम्नलिखित आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी:

क. प्राधिकारी प्राथमिक जांच परिणाम जारी किए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर सभी ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों से प्रारंभिक जांच परिणाम पर टिप्पणियां आमंत्रित करते हैं। उनसे प्राप्त टिप्पणियों की अंतिम जांच परिणाम में जांच की जाएगी।

ख. प्राधिकारी सभी हितबद्ध पक्षकारों को जांच से संगत उनके विचार प्रस्तुत करने के लिए अवसर प्रदान करने हेतु मौखिक सुनवाई आयोजित करेंगे। मौखिक सुनवाई के दौरान उठाए गए मुद्दों और चिंताओं की अंतिम जांच परिणाम में जांच की जाएगी। मौखिक सुनवाई की तारीख डीजीटीआर की वेबसाइट (dgtr.gov.in) पर घोषित की जाएगी।

ग. प्राधिकारी आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन करेंगे।

भूपिन्दर एस. भल्ला, अपर सचिव एवं महानिदेशक

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION
PRELIMINARY FINDINGS

New Delhi, the 11th May, 2020

Case No. SG-08/2019

Subject : Preliminary Findings of Bilateral Safeguard Investigation concerning imports of “Phthalic Anhydride” into India from Korea under India-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017

F. No. 22/8/2019-DGTR.—A. BACKGROUND OF THE CASE

1. Having regard to the Article 2.22 of the Comprehensive Economic Cooperation Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of Korea (CEPA) and India-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017 (hereinafter referred to as the “Rules” or “Bilateral Safeguard Rules”) thereof, M/s I G Petrochemicals Limited and M/s Thirumalai Chemicals Ltd. (herein after referred to as the “applicants”) have filed an application before the Director General of Trade Remedies (herein after referred to as the “Authority” or “Director General”) in accordance with CEPA and Bilateral Safeguard Rules for initiation of bilateral safeguard investigation concerning increased imports of Phthalic Anhydride (PAN) (herein after referred to as the “product under consideration” or “subject goods”) from Korea RP (herein after referred to as “subject country”).
2. The Authority on the basis of the prima facie evidence submitted by the Applicants, issued notification number SG-08/2019 dated 1st October, 2019, published in the Gazette of India, initiating the investigation in accordance with the rules.

B. Procedure

3. The procedure described below has been followed with regard to the investigation-
 - a. The Authority sent a copy of the initiation notification dated 1st October, 2019 to the Central Government in the Ministry of Commerce and Industry and other Ministries concerned, Government of Korea through Embassy of Republic of Korea in India, the known producers and exporters in the subject country and known importers and other interested parties as mentioned in the application, in accordance with Rule 5(2) of the said Rules.
 - b. Copy of the non-confidential version of the application filed by the Applicants was made available to the Central Government in the Ministry of Commerce and Industry and other Ministries concerned, Government of Korea through Embassy of Republic of Korea in India and the known producers and exporters in the subject country in accordance with Rule 5(3) of the Rules.
 - c. The Authority forwarded a copy of the public notice initiating bilateral safeguard investigation to the following known producers / exporters in the subject country and provided them an opportunity to file response to questionnaire in the form and manner prescribed and make their views known in writing within thirty days in accordance with the Rules 5(4) of the Rules:
 - i. Aekyung Petrochemical Co. Ltd.
 - ii. LG Petrochemical, Yeochon.
 - iii. Hanwha Chemical Corporation
 - iv. OCI Company Limited
 - d. In response to the questionnaire issued, all four producers/exporters filed exporter's questionnaire response.

- e. The Authority sent Importer Questionnaires to the following known importers / users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 5(4) of the Rules:
- i. Cray Valley Resins India Ltd.
 - ii. Goodless Nerolac Paints Ltd.
 - iii. Gargi Industries
 - iv. Hindustan Insecticides Limited
 - v. Kemrock Industries & Exports Ltd.
 - vi. Shalimar Paints Limited,
 - vii. U.K. Paints India Pvt. Ltd.
- f. In response, the following importers have filed questionnaire response:
- i. Sandeep Organics Private Ltd
 - ii. Unity Organics Pvt Ltd
 - iii. Nishant Organics Pvt Ltd
 - iv. Dhanlaxmi Pigments Pvt Ltd
 - v. Kesar Petroproducts Ltd
 - vi. Mazda Colours Ltd
 - vii. Shiv Dyestuff Intermediate Industries
 - viii. A-One Phthalo Colours Pvt Ltd
 - ix. A-One Chemicals
 - x. Narayan Organics Pvt Ltd
 - xi. Narayan Industries
 - xii. PCL Oil & Solvents Ltd
 - xiii. KLJ Plasticizers Ltd
 - xiv. Rachna Plasticizers
 - xv. Payal Polyplast Pvt Ltd
 - xvi. Asian Paints Limited
 - xvii. Kansai Nerolac Paints Limited
 - xviii. Shalimar Paints Ltd
 - xix. Bergen Paints India Ltd
- g. The Authority also sent questionnaire to the domestic industry. The domestic industry filed its questionnaire response.
- h. The following interested parties filed submissions responding to the initiation notification:
- i. Chemexcil (Basic Chemicals, Cosmetics & Dyes Export Promotion Council)
 - ii. The Gujarat Dyestuff Manufacturers Association
 - iii. Korea Petrochemical Industry Association on behalf of Aekyung Petrochemical co Ltd., Hanwha Chemical Corporation, OCI Company Ltd., LG Chem Ltd.,
 - iv. Government of Korea
 - v. Indian Paint Association
 - vi. Collective Submissions on behalf of KLJ Plasticizers Ltd., Payal Polyplast Pvt Ltd., Rachna Plastics and PCL Oil & Solvents Ltd.

- i. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.
- j. The submissions made by the interested parties so far, wherever found relevant, have been considered while issuing these preliminary findings.

C. SUBMISSIONS MADE BY THE APPLICANTS

- 4. The submissions made by the applicants are as follows:
 - a. The product under investigation is “Phthalic Anhydride”, falling under the HS code 29173500. Product under consideration is commonly used to produce Phthalate esters, which function as plasticizers.
 - b. The product being produced by the domestic industry is like article to imported product. The domestic product is comparable to the imported product.
 - c. Apart from the applicants, there are two existing producers in India namely; SI Group Limited and Asian Paints. Asian Paints has permanently shut down their plant in July 2017 and their plant has been bought out by one of the applicants; M/s Thirumalai Chemicals Ltd.
 - d. Pursuant to India Korea CEPA, the duty on imports of Phthalic Anhydride from Korea has been reduced to zero over 8 years.
 - e. There is significant increase in the import volumes. Imports of product concerned into India increased significantly in absolute terms and in relation to production, consumption and share in imports.
 - f. Imports into India from Korea has duty advantage for Phthalic Anhydride under India –Korea CEPA Agreement, so the country is now flooded with subject goods from Korea.
 - g. Production and sales of the Indian industry has declined significantly in the most recent period. While the demand for the product has not increased, the imports have surged, thus adversely impacting the sales volume of the domestic industry.
 - h. Capacity utilization of the industry has declined in Q1 of 2019-20.
 - i. From the decline in production and capacity utilization it is evident that the increase in imports is causing injury to the domestic industry.
 - j. Market share of domestic industry has declined whereas market share of the imports has increased. Market share fell sharply below to 50% Q1, 2019-20).
 - k. The subject imports are significantly undercutting the prices of the domestic industry. The import prices have declined sharply in the last two quarters of POI. Thus, if the imports keep on increasing, the domestic industry will not be able to recover even processing costs and would incur significant financial losses.
 - l. The profits of the domestic industry have declined from Rs. *** Lacs in Q2 2018-19 to Rs.*** Lacs in Q1 2019-20, considering loss of sales during this period. The profits of the industry were increasing till Q2 2018-19.
 - m. The productivity of the Indian industry has improved initially but declined significantly in the POI.
 - n. In addition to the serious injury already caused, imports are threatening serious injury as would be obvious from the following-
 - i. The volume of imports has increased significantly in a relatively short period.
 - ii. Significant share in the domestic market is already held by the imports and the share of imports is increasing.
 - iii. The difference between domestic price and imported product price is quite significant.
 - o. There are no factors other than increased imports that can be attributed to the serious injury caused to the domestic industry.

- p. The landed price of imports is significantly lower than the selling prices of the domestic industry.
 - q. The domestic industry is losing sales opportunities as well as normal margin. Consequently, sales, profits, return on investment and cash flow is declining due to continued presence of low-priced imports.
 - r. Increased imports have led to increase in market share of imports and reduction in market share of the domestic industry.
 - s. It is submitted that the imports from Korea have increased significantly whereas the production, sales and resultantly the capacity utilization of Indian industry has declined significantly.
 - t. With regard to adjustment plans, the domestic industry has submitted that it is taking measures to reduce costs. IG Petrochemicals has given an adjustment plan which includes action on reduction in raw material cost by replacing existing catalyst, improvement in recoveries reduction in power and fuel cost, capacity additions and integrating utilities of existing plants, efforts to reduce costs on account of administrative overheads, personnel cost and finance cost. Thirumalai Chemicals has given an adjustment plan which includes reduction in cost by upgrading equipment for higher capacity & efficiency, improvement in yield, reduction in energy costs, reduction in oil consumption, reduction in wages & salaries, stores & spares, repair & maintenance and administrative overheads.
5. The submissions made by Korea Petrochemical Industry Association are as follows:
- a. The application does not contain any evidence to satisfy the requirements of the Rules.
 - b. Key performance parameters of the domestic industry such as capacity utilization, production, sales, profitability do not show any injury.
 - c. The Applicants have failed to demonstrate that the alleged injury is due to the increase in imports and the reduction in custom duties. It has not been shown that the increase in the imports is due to the reduction or elimination of the custom duties and increase alone is the cause of injury to the domestic industry requirement of Article 2.22 of the India-Korea CEPA.
 - d. Delay in planned capacity expansions, planned short term shut-downs, volatility in the ox (Orthoxylene) prices, etc. may also have impacted the performance of the Applicants.
 - e. The discussions in the annual reports of the Applicant do not show any sign of overall deterioration in the situation.
 - f. The Applicant should provide data for the injury period determined by the Authority. The period for which data is provided in the Application is misleading.
 - g. There has been an increase in imports from Thailand and Indonesia as well with whom India has FTA. Further, increase in imports from Taiwan is also in line with increase in imports from Korea.
 - h. The increase in imports coincides more with the expiry of the anti-dumping duty on the imports from China PR, Indonesia, Israel, Russia, Taiwan, Thailand and UAE, than the reduction in the custom duties under CEPA. The application is silent on the effects of expiry of anti-dumping duty as a reason for increase in imports.
 - i. Imports were necessitated to meet the demand supply gap.
 - j. The Applicants had claimed dumping as a cause of injury till the period September 2017.
 - k. While imports from Korea RP constituted about 23% of the Indian demand, other imports held about 24% demand.
 - l. The production of DI has increased. This is in spite of various issues such as volatility in cure oil and other petrochemical products, slow-down in Far East, US-China Trade sanction etc, delay in completing the expansions to meet the demand etc.
 - m. Sales of the DI also increased in the latest period in comparison to 2007-08 by 38 points

- n. There has been an increase in the capacity of the domestic industry. Additions in capacity at a time when the DI is claiming serious injury should be seen as factor demolishing the injury claims of the DI.
- o. The production expansion plans of the Applicants is a sign of DI's judgment that there shall be increase in production and sales volume in the near future which guarantees that there is no serious injury that has been claimed by the domestic industry. In reality there is a positive outlook.
- p. The import prices have increased following the trend of increase in prices of the domestic industry. The landed price of imports evidently had not forced the DI to reduce its prices. On the contrary, NSR has gone up.
- q. Domestic industry was earning high profits when anti-dumping duty was in force. The fall in current profits is not a decline but correction of abnormally high profits.
- r. There have been two safeguard measures and anti-dumping measures in about 10 years, and the Applicants rely on import restrictions through trade remedies rather than devising any strategy to improve their performance.
- s. In the ADD investigation concluded recently, negative determination on injury was done and likelihood of injury was also ruled out.
- t. The initiation nowhere discloses whether domestic industry has submitted any adjustment plan as to how they will achieve increase in productivity, decrease in cost and above all reduction in their selling prices to meet international competition.
- u. There should be an unforeseen development which should have caused increase in imports.

D.2 Submissions made by the Korean Government

6. The submissions made by the Korean Government are as follows: -

- a. The current circumstances of the Indian domestic industry do not qualify for critical circumstances requiring imposition of provisional safeguard measures as defined under Article 2.24 of Korea – India CEPA.
- b. The present investigation should be terminated on the procedural ground as the domestic industry has not provided any adjustment plan.
- c. The analysis of economic parameters does not make out a case for injury or threat of injury to the domestic industry.
- d. There has been no recent, sudden, sharp, and significant increase of imports of phthalic anhydride from Korea RP.
- e. Any alleged increased in imports is not consequential to the reduction or elimination of the customs duties under the Korea-India CEPA.
- f. The present investigation should be terminated as the substantive requirements of a valid bilateral safeguard measure have not been satisfied as the standards required for a safeguard investigation are much higher.
- g. The Applicants have claimed excessive confidentiality in their Application as the data which was available in the final finding of the anti-dumping investigation has not been disclosed. Further, the requirements of the trade notice 10/2018 have not been complied with.
- h. The application is deficient as the data provided by the domestic industry does not correspond to the period identified in the initiation notification.
- i. The imports from other countries have increased at a faster rate as compared to imports from Korea.
- j. As per Article 3.1 of the Agreement on Safeguards, there must be a reasoned and adequate explanation which demonstrates the connection between the reduction of the duty and the alleged increase in imports. Authority should identify and provide a reasoned explanation and demonstration of the same.

- k. There is no sudden, significant or sharp increase in the imports as per the language of Article 2.1 of the Agreement on Safeguards and the Article 2.22 of the Korea- India CEPA.
- l. The 4 requirements of the Article 2.22 of the Korea- India CEPA have not been complied with and hence the investigation shall be terminated.
- m. The imports could have also increased as a result of expiry of the anti-dumping duty on the imports from Israel, Korea and Taiwan.
- n. The performance of the Applicants has increased in terms of production, sales, market share, inventories, profits, cash profits, etc.
- o. In compliance with the Article 4.2(b) of the agreement and Rule 7 of the rules, the Authority is required to examine causal link between the increase in imports and injury and do the non-attribution analysis.
- p. The imposition of the duties would weaken the economic ties of the two countries.

D.3 Submissions made by the Indian Paint Association

- 7. The submissions made by the Indian Paint Association are as follows: -
 - a. The Applicants have not brought forward sufficient evidence to prove the conditions for initiation of the bilateral safeguard investigation. The four conditions laid down in Article 2.22 are not satisfied.
 - b. The Applicant has not provided the data for the period as decided in the initiation notification.
 - c. The application does not allow a reasonable understanding of the allegations as it fails to meet the standards laid down in Trade notice no. 10/2018.
 - d. The trade notice issued by DGTR is applicable for all trade remedy investigations.
 - e. The Applicants have not provided the adjustment plan as required under Rule 4(2)(b) of the Bilateral Safeguard Rules.
 - f. The alleged increase is not a result of the reduction or elimination of the custom duties as is required under Article 2.22 of the Korea- India CEPA.
 - g. The standards of “serious injury” under the Agreements on Safeguards is “very high” and “exacting”.
 - h. All the factors listed down in Article 4.2 (a) have to be examined for evaluation of injury.
 - i. As per the Applicants annual reports, the volatility in the prices of the Ortho-Xylene, shut down of plant for maintenance etc have also impacted the performance of the industry.
 - j. There is absence of causal link in the investigation. The Authority should examine causal link and perform non-attribution analysis.
 - k. There has been a sharper increase in imports from ASEAN countries as compared to the subject imports. Therefore, serious injury alone cannot be attributable to subject imports alone.
 - l. The domestic industry does not have the ability to meet the domestic demand. The imports from Korea RP have increased with the increase in demand.
 - m. The imposition of duty will allow the Applicants to create dominant position for itself in the market and create barriers for new entrants.
 - n. There is no “such recent, sudden, sharp and significant increase in quantities” in line with Article 2.22 of CEPA and decision of WTO Appellate Body in Argentina Footwear and US Steel Safeguards cases.
 - o. There are no critical circumstances which warrant the need of imposition of provisional safeguard duty.
 - p. The requirement of injury in the safeguards is high. The overall position of the domestic industry is to be substantially evaluated and as per WTO Appellate body they should be ‘at minimum’.
 - q. Significant imports are happening under Advance Authorization Scheme.

- r. Article 4.2(b) requires the Authority to distribute the effects of increase in imports and demonstrate the causal link and ensure non-attribution analysis.
- s. Contrary to the allegation by the petitioners that the “demand of the product has not increased”, there is a positive trend in demand.
- t. As against the claim made by the Applicants, the volume of imports from other countries have increased.
- u. The increase in selling price is more than the increase in landed price.

D.4 Submissions made by Chemexcil (Basic Chemicals, Cosmetics & Dyes Export Promotion Council)

8. The submission made by Chemexcil is as under: -

The imposition of the duty will lead to increase in the price of the imported product which will eventually lead to increase in the prices by the local producers.

D.5 Submissions made by the Gujrat Dyestuff Manufacturers Association

9. The submissions made by Gujrat Dyestuff Manufacturers Association are as follow: -

- a. The petition did not provide any appropriate evidence to substantiate the grounds for initiation of safeguard investigation satisfying the requirements of CEPA.
- b. The reduction or elimination of the customs duty was not even a remote cause of the increase in the imports and no evidence has been provided to substantiate the contention that domestic industry suffered “serious injury”.
- c. The impact of imports from other countries and expiry of Anti-dumping duties on Korea, Taiwan and Israel is not explained in the petition.
- d. There has been an increase in imports at comparable level to Korea RP from Thailand and Indonesia with which India has signed FTA and other countries.
- e. The price of imports from Korea was higher as compared to prices of imports from other countries.
- f. As per the disclosures in the annual reports in the petition, there has been production cut and increase in imports were necessitated to meet the demand supply gap.
- g. The CEO of TCL has mentioned in one of his speech that there was lower production and higher costs as the major revamp project was underway.
- h. As per the Investor’ presentation of IGPL in August 19, the imports have increased in last 3 years on back of high domestic demand.
- i. The impact of closure of Asian Paints Plant has affected the decline in production and increase in imports, not the reduction of custom duty.
- j. The petitioners are unable to produce and supply as there is a slow growth in the production of ortho-xylene which might have led to domestic industry finding it difficult in getting raw materials.
- k. The management speech by Thirumalai Chemicals Limited on 25th July, 2019 stated with regard to performance in FY 2018-19 that “the first half of the financial year was outstanding in every parameter”. It has also been stated that the customers in downstream industries started destocking and the prices were driven further down by the knee-jerk reaction of nervous bankers.
- l. In the Managing Director’s speech of IG Petrochemicals Ltd., it was said that “the year 2018 was marked by volatile crude oil prices which inflated the raw material prices for PA as well”.
- m. The injury data in the presented in the petition do not show any “serious injury”.

- n. The injury period considered for the purposes of present investigation is from April, 2015 to June 2019 and as per the initiation notification but the injury data is not available for this period.
- o. The petitioners have claimed dumping as a cause of injury till the period September 2017.
- p. The data for the latest quarter could have annualized instead of converting previous years into equivalents of a quarter which is not a fair approach.
- q. The production of DI has increased by 13 points in the latest period despite various issues such as volatility in crude oil and other petrochemical products, slow-down in Far-East, US-China Trade sanction etc, delay in completing the expansions to meet the demand etc.
- r. Sales of the DI also increased by the latest period in comparison to 2007-08 by 38 points which shows DI did not suffer any injury.
- s. There has been an increase in the capacity by 26 points of the domestic industry. The additions in capacity is the cause of serious injury should be seen as factor nullifying the injury claims of the DI.
- t. The price undercutting claimed by the DI is redundant as the same could be on basis of a high NSR charged by DI themselves.
- u. The inventory remained in the range of *** MT over the years, shows no injury now.
- v. As per given data, there is decline in profitability after Q1 2018-19, when ADD on imports of PUC from Korea, Taiwan and Israel was rescinded. It is not a decline in profitability parameter but correction of abnormally high profits.
- w. There is no causal link between alleged increase in imports from Korea RP and for the reasons contented and injury claimed.
- x. The domestic industry has not submitted any adjustment plan.
- y. The purpose of bilateral safeguard duty is to benefit public at large however, as there is demand supply gap in India the present investigation is not in public interest.

D.5 Submissions made by the KLJ Plasticizers Ltd, Payal Polyplast Pvt Ltd, Rachna Plastics and PCL Oil & Solvents Ltd.

10. The submissions made by KLJ Plasticizers Ltd, Payal Polyplast Pvt Ltd, Rachna Plastics and PCL Oil & Solvents Ltd are as follow: -
- a. The petitioners failed to provide evidences to justify that the increase in imports from Korea RP is because of reduction in customs duties.
 - b. The impact on the domestic industry of increase in imports from Thailand and Indonesia, with which India has signed FTA, is not explained. The imports have increased from Taiwan and Israel as well.
 - c. The increase in imports may have happened due to the expiry of the anti-dumping duty and not because of reduction in customs duties. Further, the domestic industry was in huge profits at the time of duty, which may have been corrected now.
 - d. There is a demand-supply gap in India which is also causing the increase in imports.
 - e. The domestic industry is facing difficulties in supply of the subject goods because of revamp of production capacities, volatility in Orthoxylene prices, delay in planned capacity expansions, planned shutdowns for short periods etc.
 - f. IGPL's investors stated in a presentation on August 19 that "the imports have increased in last 3 years on back of high domestic demand".
 - g. The domestic industry is incapable to fulfil the demand which led to increase in imports from other countries.
 - h. Further, as per IGPL, "there was a planned shutdown of our PA 2 Plant as it required a catalyst change".
 - i. The TCL CEO mentioned in his speech that "the major revamp project underway in India led to lower production and higher costs".
 - j. The Asia Paints plant shut down in July 2017 impacted the production of PAN in India.

- k. The Applicants have faced raw material issue as well as there was capacity revamp which could have impacted the production.
- l. The speech by promoter of Thirumalai Chemicals Limited on 25th July, 2019 stated that the first half of the financial year was outstanding in every parameter but there was a slowdown in the months followed. The customers in downstream industries started destocking and the prices were driven further down.
- m. Managing Director's Speech of IG Petrochemicals Ltd. said that "the year 2018 was marked by volatile crude oil prices which inflated the raw material prices for PA as well".
- n. The injury data does not show any serious injury and there has not been any impairment in the situation of domestic industry.
- o. The petitioners should be directed to provide injury data for the injury period as decided by the Authority as the data provided in the petition does not fulfil the data requirement by the Authority.
- p. The injury period in the petition is not same which is determined by DG hence, objective examination of injury is not possible.
- q. The imports from Korea increased from 2007-2019. However, the imports from other countries increased drastically in the same time period which clearly shows that imports have increased from all the countries and the claim that imports from Korea increased due to reduction of customs duty has no basis.
- r. Due to the supply constraints of OX(Orthoxylene) , the production of DI may have been impacted. Also, volatility in cure oil and other petrochemical products, slow-down in Far East, US-China Trade sanction etc, delay in completing the expansions would have contributed.
- s. The domestic industry did not justify their claim of serious injury as there is increase in its volume and price parameters.
- t. Price undercutting was 0-5% positive in the sunset investigation. However, it was found that domestic industry did not suffer any injury. The landed price of imports evidently had not forced the domestic industry to reduce its prices and on the contrary NSR has gone up
- u. The petitioners could not establish any causal link between alleged increase in imports from Korea and Injury claimed by DI.
- v. The application contains no adjustment plans on how the Applicants are planning to correct their present situation to achieve increase in productivity, decrease in cost and correction in selling prices to meet international competition.
- w. The substantial part of imports was necessitated to meet the demand- supply gap and if any bilateral duty is imposed that would be against the public interest.

D. EXAMINATION BY THE AUTHORITY

- 11. The information made available by the interested parties in their submissions, have been considered by the Authority for the purpose of the present determination. The Authority has examined views of interested parties and has appropriately considered the same for the purpose of the preliminary findings.
- a. The Authority notes that the application contains data for the period April, 2007 to June, 2019. Further, while responding to initiation, the Applicants have provided data for the period up to Sept, 2019. Thus, the interested parties have access to the relevant information and an opportunity to comment on information for the period from April, 2007 to Sept., 2019. The Authority has considered the period from April, 2015 to Sept., 2019 for the purpose of examining increased imports and serious injury to the domestic industry. However, since the interested parties have contended that the Authority is required to consider whether the increase in import is as a result of tariff concessions under the Agreement and are consequently causing injury, the Authority has considered the information contained in the application for the period from April, 2007 to June, 2019 to determine whether the increased imports are a result of tariff concession. The period July-Sept., 2019 has also been added considering that this is a safeguard investigation and the Authority in the past has added data for subsequent period, post-initiation, of investigation.

- b. As regards adjustment plan, the Authority notes that while the same is relevant for duration of duty, and not at the stage of preliminary determination, the domestic industry in any case has given an adjustment plan, after initiation of investigation.
- c. The Authority notes that the present investigation is a bilateral safeguard investigation initiated under India-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017 read with India-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement. The Authority has examined whether increased imports are as a result of tariff concessions under the agreement. For this purpose, the Authority has considered imports of the product from April, 2007 to Sept., 2019. It is seen that volume of imports has increased in absolute terms and in relation to production and consumption as the tariff concessions increased.
- d. As regards imports from non-subject countries, it is seen that the landed price of imports after adding applicable customs duties are higher from non-subject countries as compared to landed price of imports from Korea. This establishes that the imports from other countries are not the primary cause of injury to the domestic industry.
- e. As regards the contention that imports have increased because of cessation of anti-dumping duty, the Authority notes that this does not establish that the injury is not due to imports from Korea. Further, it is noted that at least one producer from Korea was not subject to anti-dumping duty.
- f. As regards the contention that imports have increased due to demand supply gap, the Authority notes that demand supply gap may, at the most, justify imports per-se. However, landed price from imports from Korea is lower than not only the selling price of domestic industry but also import price from several countries. Further, a number of countries have been supplying the product in Indian market. However, share of import from Korea shows dominant position gained by Korean imports. Further, it is seen that the domestic industry has faced decline in production and domestic sales during the relevant period. Inventory with the domestic industry have increased. These facts do not show that increased imports are due to closure of production by Asian Paints.
- g. As regards the contention that significant imports have happened under advance authorization scheme, the Authority notes that since imports are under zero duty under the Agreement, it defies the logic why would any interested party import under advance license and unnecessarily undertake export obligation when the same amount of duty exemption is available without undertaking any export obligation.
- h. The Authority notes that the present investigation is under India-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017 and India-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement.
- i. As regards statements in the annual reports of the petitioning companies, the Authority notes that the injury to the domestic industry has largely occurred in the current year. Further, published unaudited quarterly results of petitioning companies also show significant decline in profits.
- j. It has not been established by the interested parties how capacity revamps, delay in planned capacity expansions, planned short term shut-downs etc could have been a major cause of injury to the domestic industry when the information relied upon in the present data does not include any costs on these accounts.
- k. As regards volatility of crude prices, the same is a global factor and not peculiar to Indian market.
- l. As regards capacity expansion, it is noted that the performance of the domestic industry in respect of profits and ROI declined steeply in the current period when there was no addition of capacity.
- m. As regards reference to the final findings of the sunset review, it is noted that the sunset review findings are based on April, 2016 to September, 2017 as the investigation period whereas the injury in the current case is more pronounced in the most recent period and much after the POI investigated in the sunset review.
- n. It is further noted that the proposed measure will be limited to only imports from Korea. Imports from all other countries would continue to be made without any safeguard measures. Thus, source of supply shall not be curtailed as a result of the proposed measures.

E.1 Product under consideration

12. The product under consideration in the present investigation “Phthalic Anhydride” (also referred to as PAN) falling under the tariff heading 29173500 is an anhydride of Phthalic Acid and is commercially produced by catalytic oxidation of Ortho-xylene or Naphthalene
13. PAN is a colourless solid, variously referred as Phthalic Anhydride flakes, Phthalic Anhydride (98% min.), Phthalic Acid Anhydrous, Phthalic Anhydride (99.8% min), etc. Phthalic Anhydride is used to produce Phthalate esters, which function as plasticizers. It is an important chemical intermediate in plastic industry.

E.2 Domestic industry

14. The Rule 2(b) Bilateral Safeguard Measures Rules, 2007 states as follows: -

"domestic industry" means the producers –

- (i) as a whole of the like or directly competitive goods operating in the territory of India; or*
- (ii) whose collective output of the like or directly competitive goods constitutes a major proportion of the total domestic production of those goods;*

15. The present application has been filed by M/s IG Petrochemicals Ltd. and M/s Thirumalai Chemicals Ltd. SI Group Pvt. Ltd. is the only other known producer of the product in India at present. SI Group Pvt. Ltd. filed information in the prescribed format after initiation of investigations, but after expiry of the time limits. It is noted that no submissions have been made by either the Applicants or the interested parties over the scope of the domestic industry. Applicants' production constitutes a major share in gross Indian production. Therefore, the application satisfies the requirement of standing under the Rules. Thus, IG Petrochemicals Ltd. and M/s Thirumalai Chemicals Ltd. constitute domestic industry for the purpose of the present determination.

E.3 Period of investigation

16. The period considered for the purposes of present investigation, as notified in the notice of initiation, is from April, 2015 to June, 2019. Further, since this is a safeguard investigation, considering the past practice, the Authority has considered the data for the period up to Sept., 2019, being the most recent period for which the data is available.

E.4 Confidentiality

17. Rule 6 of the Rules deals with confidentiality of information. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential versions of the evidences submitted by various interested parties in the form of public file.

E.5 Customs Duty under Comprehensive Economic Partnership Agreement

18. The rate of custom duty on the imports of Phthalic Anhydride considering the concessions under the Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) was as follows: -

Custom Duty Rate			
31st Dec 2009	10.94%	2010-11	10.55%
31st Dec 2010	9.38%	2011-12	8.99%
31st Dec 2011	7.81%	2012-13	7.42%
31st Dec 2012	6.25%	2013-14	5.86%
31st Dec 2013	4.69%	2014-15	4.30%
31st Dec 2014	3.13%	2015-16	2.74%
31st Dec 2015	1.56%	2016-17	1.17%
31st Dec 2016	0.00%	2017-18	0.00%
31st Dec 2017	0.00%	2018-19	0.00%
31st Dec 2018	0.00%		

E.6 Source of information

19. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange for details of imports of subject goods. The Authority has relied upon the DGCI&S data for computation of the volume and value of imports for the required analysis.

E.7 Increased imports from Korea RP

20. Rule 2 (c) of India-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017 states:

"increased imports" includes increase in imports from the Republic of Korea whether in absolute terms or relative to domestic production;

21. The said Rules require an examination whether imports of the PUC increased in such quantities in absolute and relative terms so as to constitute "increased imports". The said Rules require an analysis of the imports, in both absolute terms and in relation to imports into India, production and consumption in India. Analysis of increased imports of the product under consideration has been conducted having regard to the said rules.

i. Imports from Korea RP in absolute terms:

22. The movement of imports is shown in the table below:

SN	Years	Import volume	Trend	Customs duty
		MT	Index	
1	2015-16	25,252	100	2.74%
2	2016-17	36,822	146	1.17%
3	2017-18	41,664	165	0.00%
4	2018-19	49,081	194	0.00%
5	Apr'19-Jun'19	22,819	181	0.00%
6	Jul'19-Sep'19	26,007	206	0.00%
7	April to Sept.,19	48,826	193	0.00%

23. It is seen that imports of the product under consideration have increased significantly in absolute terms over the period.

ii. Imports in relation to gross imports in India

24. The share of imports of subject goods from Korea RP and other countries is shown in the table below:

SN	Years	Imports in MT			Share in imports	
		Korea RP	Other countries	Total imports	Korea RP	Other countries
1	2015-16	25,252	53,866	79,118	32%	68%
2	2016-17	36,822	63,115	99,937	37%	63%
3	2017-18	41,664	88,775	1,30,439	32%	68%
4	2018-19	49,081	95,579	1,44,660	34%	66%
5	Apr'19-Jun'19	22,819	23,384	46,204	49%	51%
6	Jul'19-Sep'19	26,007	23,830	49,837	52%	48%
7	April to Sept.,19	48,826	47,214	96,041	51%	49%

25. It is seen that share of imports of the product under consideration from Korea increased over the period with the rising tariff concession whereas the share of other countries declined. Korean imports now command majority share with the duty concession increasing to its full extent. Even

when imports are being reported from a number of other countries, their share collectively is lower than share of Korea alone.

iii. Increase in imports in relation to production and consumption in India

26. The movement of imports of subject goods in relation to production and consumption in India is shown in the table below:

	Years	Korea imports	Indian Production	Demand	Imports in relation to	
					Production	Consumption
		MT	MT Trend	MT	%	%
1	2015-16	25,252	100	3,32,413	8%	8%
2	2016-17	36,822	97	3,47,995	12%	11%
3	2017-18	41,664	100	3,72,030	14%	11%
4	2018-19	49,081	97	3,82,583	18%	13%
5	Apr'19-Jun'19	22,819	91	97,163	35%	23%
6	Jul'19-Sep'19	26,007	87	1,05,209	42%	25%
7	April to Sept.,19	48,826	112	2,02,372	38%	24%

27. It is seen that imports from Korea increased significantly in relation to production and consumption in India with increase in duty concession.

E.8 Injury

28. Serious Injury is defined as follows under the Rules:

(f) *serious injury* means a significant overall impairment in the position of a domestic industry; and

(g) *"threat of serious injury"* means serious injury that, on the basis of facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility, is clearly imminent; and

29. Thus, increase in imports should be such which causes a significant overall impairment in the position of a domestic industry.

30. Rule 7 of the Rules further provides as follows:

The Authority shall determine serious injury or threat of serious injury to the domestic industry taking into account, inter alia, the following principles, namely: -

(a) the Authority shall evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry, in particular, the rate and amount of the increase in imports of the originating good in absolute and relative terms, the share of the domestic market taken by increased imports of the originating good, changes in the level of sales, production, productivity, capacity utilisation, profits and losses, and employment; and

(b) the determination under this rule shall not be made unless the investigation demonstrates, on the basis of objective evidence, the existence of the causal link between increased imports of the originating good and serious injury or threat thereof and when factors other than increased imports of the originating good are causing injury to the domestic industry at the same time, such injury shall not be attributed to increased imports of the originating goods.

31. It is noted that evaluation of the listed parameters needs to take into account peculiarities of different industries and situations. The Authority has therefore examined serious injury to the domestic industry, having regard to the facts of the present case and the situation of the industry. Thus, in addition to a technical examination of all the listed factors and any other relevant factors, it is essential that the overall position of the industry is evaluated, in light of all the relevant factors having a bearing on the situation of that industry. Accordingly, in analyzing serious injury all factors, which are mentioned in the rules as well as other factors which are relevant for determination of serious injury, have been considered. The determination of serious injury is based on evaluation of the overall position of the domestic industry, in light of all the relevant factors having a bearing on the situation of that industry.

a. Increase in imports in absolute and relative terms

32. It is seen that the imports of subject goods have increased significantly in absolute as well as in relation to production and consumption in India. It is also seen that the imports increased significantly with the full concessions given to the Korean imports.

b. Capacity, Production, Capacity Utilization and Domestic Sales

33. The details of capacity, capacity utilization and domestic sales are as follows:

SN	Years	Capacity	Production	Capacity Utilization	Domestic sales	Export Sales Trend	Korea RP imports
		MT	MT Trend	%	MT	MT	MT
1	2015-16	3,06,110	100	89%	2,18,825	100	25,252
2	2016-17	3,06,110	97	86%	2,14,580	103	36,822
3	2017-18	3,06,110	100	89%	2,24,112	98	41,664
4	2018-19	3,06,110	97	87%	2,27,235	63	49,081
5	Apr'19-Jun'19	76,528	91	82%	48,465	70	22,819
6	Jul'19-Sep'19	76,528	87	78%	52,738	92	26,007
7	Apr-Sept.,19	1,53,055	112	80%	1,01,203	81	48,826

34. It is seen that

- production and capacity utilisation of the domestic industry has declined over the period;
- whereas domestic sales of the domestic industry were increasing till 2018-19, the same have declined significantly thereafter;
- the exports have declined in 2018-19 and increased thereafter. The profitability of exports is, however, adverse as compared to domestic sales.

c. Market share of the domestic industry

35. The movement of market share was as follows:

SN	Years	Domestic industry	Korean imports	Other Producers	Other Countries	Total
1	2015-16	66%	8%	10%	16%	100%
2	2016-17	62%	11%	10%	18%	100%
3	2017-18	60%	11%	5%	24%	100%
4	2018-19	59%	13%	3%	25%	100%
5	Apr'19-Jun'19	50%	23%	3%	24%	100%
6	Jul'19-Sep'19	50%	25%	3%	23%	100%
7	April to Sept.,19	50%	24%	3%	23%	100%

36. It is seen that whereas market share of domestic industry declined, that of Korean imports increased. On overall basis, whereas the domestic industry lost 16% market share over the period, the Korean imports gained the market share by almost the same level.

d. Employment and Productivity

37. The data on employment and productivity is as follows-

SN	Year	No. of Employees	Productivity per day	Productivity per employee
		Trend	Trend MT/Day	Trend MT/Nos.
1	2015-16	100	100	100
2	2016-17	100	97	97
3	2017-18	101	100	99
4	2018-19	103	97	95
5	Apr'19-Jun'19	103	92	89
6	Jul'19-Sep'19	103	87	85
7	April to Sept.,19	103	89	87

38. The productivity per day and productivity per employee has witnessed decline in recent years. The Applicants have however submitted that performance on these accounts are dependent on a number of other parameters and is not directly linked to imports.

e. Inventory

39. The data on inventory shows as follows-

SN	Particulars	Average stock (MT) Trend
1	2015-16	100
2	2016-17	121
3	2017-18	72
4	2018-19	71
5	Q1-2019-20	140
6	Q2-2019-20	132

40. It is seen that the level of inventories with the domestic industry increased over the period.

f. Profit/loss

41. The data on profits and return on capital employed shows as follows-

SN	Year	Profit/(loss)		ROI
		Rs. Lacs Trend	Rs./MT Trend	Trend
1	2015-16	100	100	100
2	2016-17	285	291	205
3	2017-18	584	570	295
4	2018-19	407	392	216
5	Apr'19-Jun'19	104	467	53
6	Jul'19-Sep'19	-13	-54	5
7	April to Sept.,19	45	98	32

42. It is seen that the profits and return on capital employed have steeply deteriorated post 2017-18. The domestic industry has suffered financial losses in the most recent period of July to Sept., 2019.

g. Price undercutting

43. The Authority examined whether the imports from Korea were benchmarking the prices of the product in the market. For the purpose, the Authority compared the landed price of imports from various countries with the landed price of imports from Korea and selling price of domestic industry.

SN	Year	NSR	Landed price	Price Undercutting	Price Undercutting
		Rs/MT Trend	Rs/MT	Rs/MT	%
1	2015-16	100	56,387	*****	0-10%
2	2016-17	113	60,274	*****	5-15%
3	2017-18	119	66,989	*****	0-10%
4	2018-19	135	74,225	*****	0-10%
5	Apr'19-Jun'19	126	68,900	*****	5-15%
6	Jul'19-Sep'19	112	63,618	*****	0-10%
7	April to Sept.,19	119	66,086	*****	0-10%

44. It is seen that the landed price of imports have been below the selling price of the domestic industry. Imports were thus undercutting the domestic industry prices.

45. The Authority examined the trends in cost of production, selling price of the domestic industry with the landed price of imports from Korea. It is seen that whereas the landed price of imports were earlier above the cost of sales, in the recent period, the landed price of imports are below the cost of sales. Had the domestic industry sold at these import prices, it would have suffered losses in the current period.

SN	Year	Cost of Sale	Selling price	Landed price
		Rs/MT Trend	Rs/MT Trend	Rs/MT
1	2015-16	100	100	56,387
2	2016-17	105	113	60,274
3	2017-18	99	119	66,989
4	2018-19	123	135	74,225
5	Apr'19-Jun'19	127	126	68,900
6	Jul'19-Sep'19	118	112	63,618
7	April to Sept.,19	122	119	66,086

E. Conclusion

46. It is provisionally concluded that the imports of the product under consideration have increased significantly in absolute terms and in relation to gross imports in India, Indian production and consumption. As a result of significant surge in imports from Korea RP, the domestic producer has suffered serious injury in terms of decline in production, sales, capacity utilization, market share, profit, ROI and rising less profitable exports and rising inventories. Considering the performance of the domestic producer in respect of various parameters, it is provisionally concluded, pending further investigations that the domestic industry has suffered serious injury as a result of duty concessions granted to Korean imports leading to increased imports of the product under consideration from Korea at low prices.

F. Threat of Serious Injury

47. The Rules provides as follows:

“threat of serious injury” means serious injury that is clearly imminent and shall be determined on the basis of facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility;

48. It is noted that imports of subject goods from Korea are entering the Indian market in significant increased quantities in absolute terms as well as in relation to production and consumption in India. The domestic industry's capacity was underutilized and the intensified imports from Korea has adversely impacted the situation. Considering the difference between the landed price of imports of subject goods, the huge capacities with Korea coupled with the fact of their high export orientation it is evident that the subject goods from Korea are likely to remain price attractive, posing continued threat of injury to the domestic industry. The threat of serious injury is established by the following factors: -

- a. The price difference between the domestic and imported product has led to increase in imports of subject goods from Korea;
- b. The producers from Korea are holding significant unutilized capacities, as established by the questionnaire response filed by the Korean producers. Resultantly, producers from Korea are continuously looking for additional markets;
- c. There is an increase in exports from Korea to India and decline in exports to the rest of the world;
- d. The demand of the product is growing and the Indian market is large and price sensitive.

49. In view of above it is provisionally concluded that the increased imports of subject goods from Korea have caused serious injury to the domestic industry. Further, the domestic industry is faced with continued threat of serious injury from imports from Korea.

G. Causal Link

50. A comprehensive evaluation of performance of the domestic industry, as brought out hereinabove demonstrates that domestic industry has suffered serious injury and is threatened with further serious injury by increased imports from Korea. The Authority examined whether the injury to the domestic industry is due to duty concessions and consequent increase in imports from Korea. Further, in view of the arguments of the interested parties that the Authority is required to examine whether the claimed injury is on account of duty concessions or some other factors, the Authority also considered the performance of the domestic industry over longer period, including the period when there was no duty concession. Relevant information on this account is contained in the application filed by the domestic industry, which is also accessible to the interested party through non-confidential version of the application and submissions.

- a. The Authority examined whether any other factor could have caused serious injury to the domestic industry. The Authority considered various known parameters and parameters brought by the interested parties and concluded that the reported injury to the domestic industry is not due to possible existence of other factors operating at the same time.
- b. The imports of product from Korea have increased significantly with increase in tariff concessions to the Korean imports and its eventual elimination of customs duty.
- c. With full duty concessions, the landed price of Korean import is lower than the selling price of the domestic industry. It was the Korean prices which were benchmarking the prices of the product in the market.
- d. The capacity utilization of the domestic industry is below the optimum level and as a result production has declined. The production and domestic sales of the domestic industry have in the recent period declined with rising imports as a consequence of duty concessions. The decline in domestic sales and rising inventories are a result of increase in imports in India.

51. It is thus evident that injury to the domestic industry has been caused by the increased imports and there is a causal link between increased imports of subject goods from Korea and serious injury and threat of serious injury to the domestic industry as a result of duty concessions granted to Korean imports.

H. Critical Circumstance

52. Rule 8 of Bilateral Safeguard Rules provides that the Authority shall proceed expeditiously with the conduct of the investigation and in critical circumstances, where there is clear evidence that increased imports have caused or are threatening to cause serious injury to the domestic industry and where delay in imposition of provisional bilateral safeguard measure would cause damage to the domestic industry which would be difficult to repair, the Authority may record a preliminary finding regarding serious injury or threat of serious injury to the domestic industry as a result of increased imports of an originating good. The Authority holds that the following facts establish the existence of critical circumstances warranting imposition of interim safeguard measures.
- With duty concessions increasing to full extent in 2017-18, imports of the product surged to 32% in 2017-18 and to 34% in 2018-19 and 49% in April 2019 – June 2019 and have remained at high levels thereafter.
 - With significant duty concessions during the present period, the domestic industry profits have declined significantly and turned into losses in Q2, 2019-20.
 - The production and sales of the domestic industry have declined despite increase in domestic demand of the product.
 - Market share of the domestic industry has declined significantly.
 - As a result, domestic sales of the domestic producer declined significantly in the most recent period (April -Sept., 2019 period). Further, profitability of the domestic industry has also suffered significantly in this period and incurred losses in Q2, 2019-20. The sales volumes in April to Sept., 19 were 8% lower than volumes sold in 2015-16.
 - The domestic industry has been forced to export the subject goods at a price lower than the domestic selling price.
53. It is noted that the factors present constitute critical circumstances and are affecting the overall performance of the domestic industry, justifying imposition of provisional bilateral safeguard measure.

I. Adjustment plan

54. Applicants have provided details of the adjustment plan during the course of the investigation. The Domestic Industry has quantified that it shall take measures directed towards reducing costs on a number of accounts. The domestic industry has submitted that it is taking measures to reduce costs. IG Petrochemicals has given an adjustment plan which includes action plan on reduction in raw material cost by replacing existing catalyst, improvement in recoveries, reduction in power and fuel cost, capacity additions and integrating utilities of existing plants, efforts to reduce costs on account of administrative overheads, personnel cost and finance cost. Thirumalai Chemicals has given an adjustment plan which includes reduction in cost by upgrading equipment for higher capacity & efficiency, improvement in yield, reduction in energy costs, reduction in oil consumption, reduction in wages & salaries, stores & spares, repair & maintenance and administrative overheads. The Authority considers that the Applicants have drawn an adjustment plan to become competitive vis-a-vis Korean imports.

J. Conclusion and Recommendation

55. On the basis of the preliminary determination above, it is provisionally concluded that increased imports of subject goods have caused serious injury and also threat of serious injury to domestic producers. It is considered that critical circumstances exist where delay in imposition of safeguard measures would cause irreparable damage to the domestic producers. With regard to imposition of bilateral safeguard measure, Rule 9 of India- Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017 states as follows:

(1) The Central Government, on the basis of the preliminary findings of the Authority, may-

(a) suspend further reduction of any rate of customs duty on the originating good provided for under the Trade Agreement; or

(b) increase the rate of customs duty on the originating good to a level not to exceed the lesser of:

(i) the Most Favoured Nation applied rate of customs duty on the originating good in effect at the time when the bilateral safeguard measure is taken; and

(ii) the Most Favoured Nation applied rate of customs duty on the originating good in effect on the day immediately preceding the date of entry into force of the Trade Agreement.

(2) The bilateral safeguard measure under sub-rule (1) shall remain in force only for a period not exceeding two hundred days from the date of its imposition.

56. After examining the above, it is considered appropriate to recommend provisional bilateral safeguard measure in terms of Rule 9 of India-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017. Accordingly, pending final determination, the Authority provisionally recommends increasing the rate of customs duty on imports of subject goods originating in Korea RP to the level of MFN duty on the subject goods as on the date of application of the bilateral safeguard measure or MFN duty on the subject goods on the day immediately preceding the date of entry into force of the Trade Agreement, whichever is less.

57. The provisional bilateral Safeguard measure on the import of the said product, as above, is recommended for a period of 200 days (two hundred days).

K. FURTHER PROCESS

58. The following further procedure would be followed subsequent to notifying the preliminary findings:

- a. The Authority invites comments on preliminary findings from all known interested parties within 30 days from the date of issue of preliminary findings. The comments received from them would be examined in the final findings.
- b. The Authority would conduct an oral hearing to provide an opportunity to all interested parties to present their views relevant to the investigation. Issues and concerns raised during the oral hearing will be examined in the final findings. The date of the oral hearing would be announced on the DGTR website (dgtr.gov.in).
- c. The Authority would conduct verification to the extent deemed necessary.

BHUPINDER S. BHALLA, Addl. Secy. & Director General